

बिजनेस रेमेडीज

वर्ष : 11 | अंक : 178 भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा विज्ञापनों के लिए स्वीकृत

व्यापार एवं विकास की आवाज

मूल्य : 3 रुपए | पेज : 8 दैनिक www.businessremedies.com

जयपुर। गुरुवार 11 जुलाई, 2024

भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश

भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री दीया कुमारी ने विधानसभा में 2 घंटे 51 मिनट लंबा भाषण दिया। अपने पहले बजट भाषण में दीया कुमारी ने युवाओं, महिलाओं, किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं कीं।

वित्त मंत्री दीया कुमारी ने कहा राज्य को 350 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने, पानी, बिजली और सड़क सुविधाओं बेहतर करने, नियोजित शहरी विकास और किसानों को सशक्त बनाने को लेकर उनकी सरकार प्रतिबद्ध है।

बजट भाषण के दौरान दीया कुमारी ने सबसे पहले निदा फाजली का शेर पढ़ा सफर में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहां बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो...

स्वामी विवेकानंद को याद करते हुए दीया कुमारी ने कहा- बहादुर, स्पष्टवादी, साफ दिल वाला, साहसी और महत्वाकांक्षी युवा ही एकमात्र नींव है। जिस पर भविष्य के राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है।

बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने भारत रत्न विनोबा भावे को याद करते हुए कहा... वास्तविक उन्नति तभी की जा सकती है, जब उसका लाभ सभी को प्राप्त हो, न की कुछ तक ही सीमित रहे। इसी विचार को सरकार का केंद्र बिंदु बनाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि आज की सरकार का ध्येय है, नेशन फर्स्ट, सिटीजन फर्स्ट। आज की सरकार की प्राथमिकता है, वचितों को वरीयता।

वित्त मंत्री दीया कुमारी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की रचना को भी पढ़ा दूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर झरे सब पीले पात, कोयल की कूहक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं। गीत नया गाता हूं। दूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर त्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नई ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता-मिटता हूं। गीत नया गाता हूं। गीत नया गाता हूं।

राजस्थान बजट की मुख्य घोषणाएं

चिकित्सा विभाग को लेकर की गई बड़ी घोषणाएं

- मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का दायरा बढ़ाया गया, योजना में बच्चों के लिए पीडियाट्रिक पैकेज जोड़ने की घोषणा की गई
- RUHS में ट्रोमा सेक्टर बनाने की घोषणा की गई पिछले दिनों की सीएम ने अस्पताल का दौरा किया था इस दौरान अस्पताल में सुविधाओं के विस्तार के निर्देश दिए थे
- हेल्थ सेक्टर को बजट में 826 फीसदी हिस्सा
- वित्त मंत्री दीया कुमारी ने कहा कि स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता है
- चिकित्सा क्षेत्र के लिए 27660 करोड़ रुपए का प्रावधान
- कुल बजट को देखे तो 826 फीसदी हेल्थ सेक्टर की हिस्सेदारी
- वित्त मंत्री ने कहा कि चिकित्सा संस्थानों को मजबूती देना जरूरी है
- इसके तहत 1500 चिकित्सक और 4000 नर्सिंग के नए पद सृजित होंगे
- प्रदेश में राजस्थान हेल्थ डिजिटल मिशन शुरू होगा।
- PHC से लेकर बड़े अस्पताल कनेक्ट होंगे
- मरीजों का ई-हेल्थ रिकॉर्ड का संधारण किया जाएगा
- राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन शुरू किए जाने की घोषणा
- हर विधानसभा क्षेत्र में आयुष्मान सामुदायिक चिकित्सा केंद्र स्थापित किए जाएंगे
- प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक-एक आयुष्मान मॉडल सीएचसी स्थापित की जाएगी
- 1500 चिकित्सक और 4000 नर्सिंग स्टाफ की भर्ती की घोषणा
- निष्क्रिय पड़े 10 ट्रोमा सेंटर को नए उपकरण दिए जाएंगे

आंगनबाड़ी के लिए की गई घोषणाएं

- अब आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को मिलेगा दूध

- सरकार का आंगनबाड़ी केंद्रों पर सप्ताह में 3 दिन दूध देने की घोषणा
- आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार बनाने के लिए दिए जाएंगे गैस कनेक्शन
- हर पंचायत मुख्यालय पर गए आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की भी घोषणा
- आंगनबाड़ी केंद्र पर सप्ताह में 3 दिन दूध उपलब्ध करवाएगी सरकार
- प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5-5 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे
- आंगनबाड़ी केंद्र में भोजन के लिए गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाएगी सरकार
- पहले चरण में 2000 आंगनबाड़ी केंद्रों को दिया जाएगा गैस सिलेंडर

शिक्षा और युवाओं के लिए सौगात

- विद्यालयों और महाविद्यालयों में बिजनेस इनोवेशन अभियान की होगी शुरुआत
- युवा नीति 2024 लाने की घोषणा
- 5 वर्षों में 4 लाख भर्तियों का प्लान
- स्कूली शिक्षा में नवीन विषयों की होगी शुरुआत
- 1 साल में 1 लाख पदों पर भर्तियों की घोषणा
- स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा काम
- 750 विद्यालयों के भवनों की मरम्मत के लिए 100 करोड़
- छात्रावास में छात्र-छात्राओं को मैस भत्ता 3000 किए जाने की घोषणा
- विद्यार्थियों को आवासीय व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए दिया जाएगा बजट
- विश्वविद्यालय में कुलपति की जगह अब कुलगुरु की होगी पदवी
- 50 नए प्राथमिक विद्यालय खोले जाने की घोषणा
- नए स्कूल भवनों का किया जाएगा निर्माण
- युवाओं के लिए ABGC पॉलिसी लाने की घोषणा

- 5 वर्षों में इस पॉलिसी के जरिए दिए जाएंगे 50 हजार रोजगार
- ज्योतिष एवं वास्तु विज्ञान के अध्ययन के लिए जयपुर में शुरू किया जाएगा केंद्र
- 10 करोड़ की लागत से जयपुर में केंद्र शुरू किया जाएगा
- संस्कृत विद्यालय के भवन निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए होंगे खर्च
- बजट में वित्त मंत्री दीया कुमारी का बड़ा प्लान
- 'रोडवेज में होंगी नई भर्तियां'
- रोडवेज में 1650 पदों पर भर्ती करने का प्लान

सड़क परिवहन के लिए अहम घोषणाएं

- फ्लाईओवर-ब्रिज आदि के लिए 9 हजार करोड़ रुपए की घोषणा
- स्टेट हाईवे, सड़कों के साथ बाइपास, फ्लाईओवर, एलिवेटेड रोड,
- हाई लेवल ब्रिज के निर्माण व रिपेयर के लिए 9 हजार रुकी घोषणा
- हर विधानसभा क्षेत्र में 5 करोड़ की सड़कें
- 3 करोड़ के अन्य विकास कार्य की स्वीकृति जारी की गई
- 53000 किमी सड़क के निर्माण के लिए 60,000 करोड़ का बजट
- प्रदेश में 2750 किलोमीटर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे बनाया जाना प्रस्तावित
- 20 करोड़ की लागत की डीपीआर तैयार की जा रही

बजट में राजस्थान औद्योगिक विकास के लिए गई घोषणाएं

- राजस्थान अभी लेखागार का होगा डिजिटाइजेशन
- एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी लाई जाएगी
- टेक्सटाइल पॉलिसी और राजस्थान वेयर हाउसिंग पॉलिसी की भी बजट में घोषणा

- इस साल राजस्थान इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव आयोजित होगा
- सरकार शहर में को-वर्किंग स्पेस भी तैयार करवाएगी
- साथ ही प्रदेश में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब की स्थापना की जाएगी
- 200 करोड़ से जयपुर में अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना की जाएगी
- साथ ही डेटा सेंटर पॉलिसी भी लाई जाएगी
- विभिन्न स्थानों पर औद्योगिक पार्क, स्टोर मंडियों की स्थापना की जाएगी

मंदिरों के लिए गई घोषणाएं

- खादू श्याम के लिए 100 करोड़ रुपए की घोषणा
- अयोध्या और काशी की तर्ज पर खादू श्याम कॉरिडोर
- 100 करोड़ रुपए की राशि खर्च करने का प्लान
- 600 मंदिरों में त्योहारों पर साज-सज्जा की जाएगी
- इस पर 13 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे
- मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया जाएगा

जल के लिए बजट में की गई घोषणाएं

- ERCP के पहले चरण का काम शुरू हो चुका है
- राजस्थान में 6 नई पेयजल परियोजनाओं की हुई घोषणा
- 25 लाख घरों में नल से जल का लक्ष्य
- किसानों को 2 हजार रुपए सम्मान निधि शुरू की
- पेयजल के लिए 5000 करोड़ की योजना
- हर विधानसभा क्षेत्र में 20 हैंडपंप लगेंगे

ऊर्जा क्षेत्र के लिए बड़ी घोषणाएं

- स्मार्ट मीटर से हाईटैक होंगे बिजली उपभोक्ता
- प्रदेशभर में 25 लाख स्मार्ट मीटर लगाने की घोषणा
- केन्द्र की RDSS योजना के तहत लगाए जाएंगे मीटर
- ऊर्जा का बैकअप प्लान काफी जरूरी
- इसको देखते हुए ऊर्जा भण्डारण के लिए बनाई

- जाएगी नीति
- अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देना जरूरी
- सभी सरकारी कार्यालयों को सौर ऊर्जा से जोड़ा जाएगा
- 765 केवी क्षमता के बनेंगे 6 नए GSS
- इसके अलावा अन्य जगहों पर भी ग्रीड सब स्टेशनों की घोषणा
- प्रदेश में बिजली से महसूस 208 लाख घरों को जारी होंगे कनेक्शन
- राजस्थान में इस साल एक लाख 45 हजार कृषि बिजली कनेक्शन होंगे जारी
- राजस्थान में किसानों को ऑन डिमांड जारी हो सकेगा बिजली कनेक्शन

कानून एवं व्यवस्था को लेकर की गई घोषणाएं

- राजस्थान में महिलाओं और बच्चियों से छेड़छाड़ रोकने के लिए घोषणा
- निर्भया स्क्वाड की 500 बालिका पेट्रोलिंग यूनिट के गठन की घोषणा
- जयपुर, जोधपुर और कोटा सहित 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले क्षेत्रों में ट्रैफिक पुलिस में 1500 ट्रैफिक वॉलंटियर की घोषणा
- पुलिस मोबिलिटी के लिए 750 मोटरसाइकिल और 500 हल्के वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे
- नए कानून के हिसाब से जरूरी IT उपकरण उपलब्ध कराने के लिए 50 करोड़ के बजट का प्रावधान
- फोरेंसिक सिस्टम को मजबूत करने के लिए कोटा, बीकानेर और भरतपुर में रसायन खण्ड की स्थापना
- राजस्थान की जेलों में कैदियों स्टिकल अपग्रेड के लिए 25 करोड़ के बजट की घोषणा
- वित्त मंत्री ने राज्य में सीएनजी-पीएनजी पर लगने वाले वैट को 14.5 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी करने का ऐलान किया। वहीं पलैट की रजिस्ट्री पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी को 6 से घटाकर 5 फीसदी कर दिया है।

BUSINESS

न्यूज ब्रीफ

बजट 2024 पर्यटन सेक्टर को शानदार सौगातें : हुसैन खान

बिजनेस रेमेडीज/जयपुर। बजट 2024 की घोषणा में पर्यटन सेक्टर को अनेक सौगातों से नवाजा गया है। मुख्य रूप से पर्यटन बोर्ड की स्थापना जो एक महत्वपूर्ण कदम सरकार की ओर से है। राजस्थान सरकार एवं पर्यटन सेक्टर से जुड़े हुए व्यवसायों के बीच समन्वय आसान होगा। 5000 करोड़ हेरीटेज टूरिज्म, रिलिजन टूरिज्म,ग्रामीण टूरिज्म, इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म एवं वेडिंग ब्रांडिंग के लिए खर्च होंगे. जो एक ऐतिहासिक कदम है। जयपुर एयरपोर्ट को 50 लाख से 70 लाख तक की कैपेसिटी तक एक्सटेंड किया जाएगा। देश एवं विदेश के पर्यटकों की संख्या जयपुर वह राजस्थान में निश्चित रूप से बढ़ेगी। इसके साथ-साथ उदयपुर, झालावाड़, गंगानगर, भीलवाड़ा कोटा एयरपोर्ट एवं एयर स्ट्रिप को डेवलप करने का काम किया जाएगा। निश्चित रूप से इन सभी सेक्टर में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। दिल्ली के बाद भारत में दूसरा मंडपम राजस्थान में बनेगा, जिससे यहां पर बड़े स्तर पर कार्य म एवं कॉन्फ्रेंस होंगे जिससे पर्यटक सेक्टर के लिए नए आयाम पैदा होंगे। सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन नीति 2024 की घोषणा होगी जिसमें अनेक ऐसी मांग जो पर्यटन सेक्टर द्वारा लगातार की जा रही थी उनका समावेश किया जाएगा। फायर एनओसी के लिए 15 मीटर तक के भवनों की फायर एनओसी प्राप्त करने के लिए वर्तमान में निर्धारित रुपये 50 प्रति वर्ग मीटर को घटकर रु. 15 प्रति वर्ग मीटर 5 वर्ष के लिए करना होटल व्यवसाईयों को फायर एनओसी प्राप्त करने में निश्चित रूप से फायदा होगा।

अध्ययन से राजस्थान में बिजली की पहुंच और गुणवत्ता में गंभीर ग्रामीण-शहरी असमानताएं उजागर हुईं

30 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को प्रतिदिन 12 घंटे से भी कम बिजली मिलती है बिजनेस रेमेडीज/जयपुर। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन औसतन 12 घंटे तक बिजली कटौती होती है, जबकि राज्य के शहरी क्षेत्रों में काफी कम कटौती होती है (प्रतिदिन 0 से 6 घंटे तक)। इसके अतिरिक्त , राजस्थान में करीब 60 प्रतिशत ग्रामीण आबादी को शिकायत के बाद बिजली बहाली के लिए 6 घंटे से अधिक समय तक इंतजार करना पड़ता है, जबकि केवल 13 प्रतिशत शहरी उपभोक्ताओं को ही इतनी लंबी देरी का सामना करना पड़ता है। ये निष्कर्ष, ऑरेंज ट्री फाउंडेशन द्वारा किए गए ‘अंडरस्टैंडिंग द अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई’ शीर्षक से अध्ययन के हिस्से के रूप में जारी किया गया है। जयपुर (उत्तर), बांसवाड़ा (दक्षिण) और जोधपुर (पश्चिम) में 12 स्थानों (6 गांवों और 6 वाडों) को कवर करते हुए, अध्ययन का उद्देश्य बिजली आपूर्ति की उपलब्धता और गुणवत्ता के साथ-साथ जीवन, आजीविका और व्यवसायों पर अनिश्चित और निम्न-गुणवत्ता वाली बिजली के प्रभावों का आकलन करना था। देश भर में 100 प्रतिशत विद्युतीकरण हासिल करने के बावजूद, ग्रामीण क्षेत्रों को अभी भी बिजली की निश्चित और गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है; जिसका

नकारात्मक प्रभाव बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं, छोटे व्यवसायों के साथ-साथ दैनिक गतिविधियों पर पड़ रहा है। रिपोर्ट में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच काफी असमानता पाई गई, जहां केवल 3 प्रतिशत ग्रामीण उपभोक्ताओं को शिकायत दर्ज कराने के एक घंटे के भीतर बिजली बहाल हो जाती है, जबकि लगभग 51 प्रतिशत शहरी उपभोक्ताओं को शिकायत दर्ज कराने के एक घंटे के भीतर त्वरित बहाली का अनुभव होता है। इसके अतिरिक्त , राजस्थान में लगभग 25 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने वोल्टेज में उतार-चढ़ाव के कारण व्यवधान और उपकरण खराब होने की बात कही है। बार-बार बिजली कटौती और वोल्टेज में उतार-चढ़ाव ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका को प्रभावित किया है, जहां कृषि गतिविधियों और लघु-स्तरीय व्यवसायों के लिए बिजली की पहुंच महत्वपूर्ण है। ऑरेंज ट्री फाउंडेशन की अध्ययन प्रमुख एवं सलाहकार शोभना तिवारी ने कहा कि अध्ययन में पिछले दशक में बिजली की उपलब्धता और आपूर्ति की गुणवत्ता में व्यापक सुधार पर प्रकाश डाला गया है। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में 2015 से बिजली की आपूर्ति में वृद्धि देखी गई है। हालांकि, अभी भी कई दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहां बिजली की पहुंच अभी भी कम है।

कैसा रहा राज्य का बजट: औद्योगिक संस्थाओं, संगठन के पदाधिकारियों से जानी राय

बिजनेस रेमेडीज/ जयपुर। राजस्थान का बजट बुधवार को वित्तमंत्री व उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने पेश कर दिया है। लोक लुभावन बजट में उद्यमियों को क्या कुछ मिला। इस संबंध में औद्योगिक संस्थाओं,संगठन और कंपनियों के पदाधिकारियों से बिजनेस रेमेडीज ने राय जानी।

राजस्थान को प्रगति के पथ पर ले जाने वाला बजट



राजस्थान सरकार के वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राजस्थान की उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री दीपा कुमारी द्वारा आज विधानसभा में प्रस्तुत राज्य बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री के अध्यक्ष डॉ. के. एल. जैन व मानद महासचिव डॉ अरुण अग्रवाल ने इस बजट को राजस्थान को प्रगति के पथ पर ले जाने वाला बजट करार दिया। डॉ. के. एल. जैन ने कहा कि वसुन्धरा राजे के बाद यह प्रथम अवसर है कि राज्य की महिला वित्त मंत्री ने राज्य के विकास का एक नया खाका राज्य की जनता के समक्ष प्रस्तुत किया है। जैसा कि अपेक्षा थी इस बजट में, गॉव, गरीब, किसान, पशु पालक, महिला, उद्यमी, युवा, बेरोजगारों, वरिष्ठ नागरिकों, स्वतंत्रता सेनानियों, पत्रकारों, छात्र-छात्राओं आदि सभी के लिए कुछ न कुछ प्रावधान किये गये हैं, जो सराहनीय हैं। बजट में अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचे, इसका सराहनीय प्रयास किया गया है।

डॉ. के. एल. जैन, अध्यक्ष, राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री

बजट में दी एम्प्लायर्स एसो. ऑफ राजस्थान की मांगों की गई पूरी



दी एम्प्लायर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान की प्रमुख मांगों बजट में शामिल की गई, जो इस प्रकार है। बैंक ऋण पर स्टाम्प ड्यूटी सिर्फ मूल दस्तावेज पर लगे, कैपिटल-ऑक्सिलरी पॉवर पर ED समाप्त व पुरानी डिमांड पर ब्याज व पेनल्टी माफ, लैंड टैक्स समाप्त, चीनी व गुड़ पर मंडी शुल्क समाप्त, 15 मीटर से कम हाइट वाले औद्योगिक व कामशियल भवनों पर फायर फेस नहीं लगेगा एवं अन्य पर भी रु.15/- प्रति 5 वर्ष (रु.3/- प्रति वर्ष) लगेगा आदि मांगों मान ली गई। दी एम्प्लायर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष एन.के. जैन ने कहा कि फायर सेस में हम और ज्यादा छूट की माँग करते हैं। साथ ही लघु उद्योगों को बिजली की दरों में कोई छूट नहीं दी गई, इस पर भी वित्त मंत्री विचार करें।

एन.के. जैन, अध्यक्ष दी एम्प्लायर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष

नई एमएसएमई पॉलिसी बहुत ही स्वागतयोग्य कदम : अरुण मिश्रा



राज्य बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए सीआईआई राजस्थान के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड एवं वेदांता समूह के कार्यकारी निदेशक अरुण मिश्रा ने कहा कि राज्य के प्रत्येक जिले को वन

डिस्ट्रीक्ट वन प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक्सपोर्ट हब बनाने की नई पॉलिसी एमएसएमई को बढ़ावा देने वाला कदम है। हथकरघा, हस्तशिल्प, एमएसएमई क्षेत्र के 3 वर्षों में 50 क्लस्टर विकसित करने का लक्ष्य, जयपुर में प्रस्तावित यूनिटी मॉल और नई एमएसएमई पॉलिसी, 2024 बहुत ही स्वागतयोग्य कदम है। उन्होंने कहा कि बजट में पर्यटन, कला एवं संस्कृति को लेकर की गई घोषणाएं जैसे दिल्ली के भारत मंडपम की तर्ज पर राजस्थान मंडपम तैयार किया जाना, काशी विश्वनाथ की तरह खादू श्याम जी मंदिर का कॉरिडोर, पुरातात्विक स्थलों और हेरिटेज स्थलों का विकास के लिए राजस्थान हेरिटेज कंवेजेशन बोर्ड बनाने की घोषणा स्वागत योग्य कदम है। यह कदम राज्य में पर्यटन और इससे जुड़े रोजगार को बढ़ावा देगा।

अरुण मिश्रा, अध्यक्ष सीआईआई राजस्थान और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड एवं वेदांता समूह के कार्यकारी निदेशक

ट्रांसफर ऑफ इंडस्ट्रीयल लैण्ड्स वेलिडेशन एक्ट सराहनीय



राज्य बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए नितिन गुप्ता, वरिष्ठ निदेशक और प्रमुख सीआईआई राजस्थान ने कहा कि रीको को हस्तान्तरित औद्योगिक श्रॉटों के भूरूपांतरण एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिये ट्रांसफर ऑफ इंडस्ट्रीयल लैण्ड्स वेलिडेशन एक्ट एक बहुत ही जरूरी कदम साबित होगा। फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट के लिए निर्धारित शुल्क को 50 रु प्रतिवर्ग मीटर से घटाकर 15 रु प्रतिवर्ग मीटर 5 वर्ष करना सभी के लिए राहत भरा कदम है।

नितिन गुप्ता, वरिष्ठ निदेशक और प्रमुख सीआईआई राजस्थान

बजट में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना सराहनीय कदम



राज्य बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए मनीष गुप्ता, चेयरमैन, इन्सोलेशन एनर्जी लिमिटेड (आईएनए सोलर) ने कहा कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में दो नए सोलर पार्क लगाए जाएंगे। एक पार्क जैसलमेर और दूसरा पूगल में बनाया जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य बढ़ाकर 33,600 मेगावाट कर दिया गया है। पीएम सूर्यघर योजना मॉडल सौर गांवों के निर्माण की सुविधा प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त बिजली रिसाव को रोकने के लिए इस वर्ष 2.5 मिलियन से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे और साथ ही प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों को सोलर एनर्जी से जोड़ा जाएगा, जो सरकार का एक स्वागत योग्यकदम है।

मनीष गुप्ता, चेयरमैन, इन्सोलेशन एनर्जी लिमिटेड (आईएनए सोलर)

विकसित राजस्थान के लिए रोडमैप तैयार करने वाला बजट



आज के राजस्थान बजट में घोषित किए गए सतत एवं समावेशी विकास के 10 स्तंभों ने विकसित राजस्थान का रोडमैप तैयार किया है। यह कहना है फिक्की राजस्थान स्टेट काउंसिल के चेयरमैन एवं कजारिया सेरामिक्स लिमिटेड के सीएमडी अशोक कजारिया का। उन्होंने बताया कि नई उद्योग नीति, निर्यात प्रोत्साहन नीति, वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति, एमएसएमई नीति एवं टेक्सटाइल नीति से औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि डिफेंस मैनुफैक्चरिंग हब, पेट्रोजोन, थीम बेस्ड इंस्ट्रियल पार्क और 50 क्लस्टर राज्य में विवेश को आकर्षित करने में सहायक साबित होंगे।

अशोक कजारिया, चेयरमैन, फिक्की राजस्थान स्टेट काउंसिल

राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड, वेडिंग टूरिज्म को बढ़ावा देना सराहनीय



राज्य बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए फिक्की राजस्थान स्टेट काउंसिल के सह-अध्यक्ष एवं शाहपुरा होटल्स के चेयरमैन सुरेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि राजस्थान विरासत संरक्षण एवं विकास प्राधिकरण राज्य की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने की दिशा में उत्त्लेखनीय पहल है। इससे ग्रामीण पर्यटन एवं कम लोकप्रिय स्थलों के विकास को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान मंडपम, राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड, वेडिंग टूरिज्म को बढ़ावा देना और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर जोर देना सराहनीय पहल है, जिससे रोजगार एवं उद्यमिता पर कई गुना सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और साथ ही पर्यटन का विकास भी होगा।

सुरेन्द्र सिंह शेखावत, सह-अध्यक्ष, फिक्की राजस्थान स्टेट काउंसिल

बजट में सभी के लिए कुछ न कुछ है



फिक्की राजस्थान स्टेट काउंसिल के सह-अध्यक्ष और अक्षय इंफ्रासिस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के सीएमडी अक्षय हाडा ने राज्य बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अतिरिक्त बिजली के लिए एमनेस्टी योजना, स्टॉप ड्यूटी, अभिन कर का युक्ति करण और आरआईपीएस को ऑनलाइन करने जैसे कदम निश्चित रूप से व्यापार करने को आसान बनाने में योगदान देंगे और उद्योग को राहत प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि बजट में सभी के लिए कुछ न कुछ है, जिसमें 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे, कोटा में एयरपोर्ट, जयपुर एयरपोर्ट की क्षमता में बढ़ोतरी,

ईआरसीपी और वेयरहाउस डेवलपमेंट जैसी पहलों के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर फोकस किया गया है, जिसका राजस्थान के विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

अक्षय हाडा, सह-अध्यक्ष, फिक्की राजस्थान स्टेट काउंसिल

उद्योग जगत के लिए उम्मीदों वाला बजट



उद्योगपति एवं समाजसेवी रिजु झुनझुनवाला ने राजस्थान सरकार के पहले पूर्ण बजट को उद्योग जगत के लिए उम्मीद वाला बजट बताया है। उद्योगपति झुनझुनवाला ने कहा कि वित्त मंत्री दीपा कुमारी ने बजट में उद्योग जगत के लिए

की घोषणाएं, उद्योग नीति 2024 लाने की घोषणा, नीति के तहत की जाएगी इंडस्ट्रीयल पार्क की स्थापना, रिसर्च, डवलपमेंट और ग्रीन टेक्नोलॉजी को दिया जाएगा बढ़ावा, निर्यात को बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी लाने की घोषणा, टैक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई पॉलिसी की घोषणा, गारमेंट एंड एप्रेल पॉलिसी लाए जाने की घोषणा, सल्लाई चेन सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए भी पॉलिसी की घोषणा, राजस्थान वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक पॉलिसी की घोषणा, बालोतरा में राजस्थान पेट्रो जोन की की स्थापना की घोषणा, प्रदेश में डिफेंस मैनुफैक्चरिंग हब की होगी स्थापना की घोषणा की है, जो स्वागतयोग्य है।

रिजु झुनझुनवाला, उद्योगपति एवं समाजसेवी

कृषि को बढ़ाने के लिये दूरगामी परिणाम परिलक्षित करता है बजट



राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दीपा कुमार द्वारा प्रस्तुत बजट राजस्थान की कृषि को बढ़ाने के लिये दूरगामी परिणाम परिलक्षित करता है। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये 650 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ बराबर मांग कर रहा था कि सरसों की खेती का रकबा बढ़ाने के प्रयास किये जाने चाहिये। यह प्रावधान समुचित जान पड़ता है। 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में दो-दो क्लस्टर का प्रावधान किया गया है। जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण हेतु जिलों में लैब खोलना प्रशंसनीय है। नयी मण्डियों के विस्तार के लिये इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिये बजट में प्रावधान किया गया है। इससे कृषि जिंसों के विपणन में सहयोग मिलेगा।

बाबूलाल गुप्ता, अध्यक्ष, राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ

श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संस्था मानसरोवर के युवा प्रकोष्ठ पदाधिकारियों ने किया वृक्षारोपण



बिजनेस रेमेडीज/जयपुर। श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संस्था मानसरोवर के युवा प्रकोष्ठ पदाधिकारियों ने वृक्षारोपण किया।



यह कार्यक्रम युवा प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष आकाश दूनीवाल के जन्मदिन के अवसर पर उनके द्वारा किया गया। उक्त कार्यक्रम हनुमान वाटिका,

पार्क सेक्टर-38, किरण पथ, मानसरोवर में आयोजित किया गया। जहां सभी युवा प्रकोष्ठ सदस्यों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया।

‘आइना अपना’

एक अच्छी सोच वाला ईंसान अपने चेहरे को आकर्षक बना लेता है साथ ही अपने दायरे में आने वाले हर आदमी की खुशियों को शतगुणित करने में साझा रहता है। मायूस का मनोमीत बनकर उसके दर्द, गम, पीड़ा को महादेव बनकर पी लेता है। उसे अमृत बांटकर हंसाते हुए जी लेता है। आइने के ऊपर आया छोटा सा स्क्वेच आपकी गुलाब सी स्माइल को फीका कर देता है। याद रखना अच्छी सोच के आइने पर स्क्वेच न आने पाए वरना तो में कई लोग ऐसे घूमते हैं जिन्हें न तो कोई पहचानता है, न कोई पहचान बनाने की कोशिश करता है। बनी हुई पहचान बनाने की कोशिश करता है। बनी हुई पहचान भी खो जाती है। कभी-कभी अच्छी सोच वाले के भी दुश्मन देखे जाते हैं क्योंकि गुलाब के साथ भी कांटे कुदरत की करामात है फिर भी गुलाब अपनी मुस्कान और महक को बरकरार रखता है।

चिंतनशीला वसुमति जी मा.सा.

‘बेड न्यूज’ के प्रमोशन के लिए जयपुर पहुंचे विक्की कौशल और एम्मी विर्क

बिजनेस रेमेडीज/जयपुर। धर्मा



फिल्म के प्रमोशन को लेकर दोनों कलाकारों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया, जहाँ उन्होंने फिल्म, अपने किरदारों और इसे लेकर अपने अनुभवों के बारे में पत्रकारों से बातचीत की। अपने अनुभव बताते हुए विक्की कौशल ने कहा कि मेरे लिए इस फिल्म की शूटिंग का अनुभव घर जैसा था, क्योंकि आनंद तिवारी और करण जोहर, जिनके साथ मैंने काम किया है, उन दोनों ने मुझे सेट पर काफी अच्छा माहौल दिया और कहानी

भी बहुत अच्छी थी। मुझे फिल्म का कॉन्सेप्ट नया लगा और इसमें कॉमेडी भी नए तरीके से पेश की गई है। फिल्म और अपने अनुभव पर बातचीत करते हुए, एम्मी विर्क ने कहा कि मेरे लिए फिल्म में काम करना बहुत अच्छा अनुभव रहा। फिल्म के ट्रेलर को लोगों के बहुत सराहा है। हमें उम्मीद है कि दर्शकों को फिल्म में हमारा काम और फिल्म दोनों ही पसंद आएंगे। इस फिल्म के लिए पूरी टीम ने खूब मेहनत की है, जिसकी झलक आपको

फिल्म में देखने को मिलेगी।

बात करें फिल्म ‘बेड न्यूज’ की कहानी की तो यह फिल्म एक ऐसी लड़की की कहानी है, जो एक रेयर मेडिकल कंडीशन का शिकार हो जाती है। इस कंडीशन की वजह से उसकी कोख में फल रहा बच्चा एक नहीं बल्कि दो अलग-अलग लड़कों का है। अब बच्चे का असली पिता कौन है इस सवाल पर लड़ाई शुरू होती है और डॉक्टर बताते हैं कि दोनों लड़के ही बच्चे के पिता हैं। इसके बाद एमी विर्क और विक्की कौशल में झगड़ा शुरू हो जाता है और तृप्त यह सोचने लगती है कि अगर चुनना ही है तो दोनों को यह साबित करना होगा कि कौन बेहतर बाप बनने के काबिल है। फिल्म तीनों कलाकारों के इर्द-गिर्द घुमती है और मजेदार दिवस्ट सामने आते हैं।

आवश्यकता

बिजनेस रेमेडीज दैनिक समाचार पत्र को कोटा, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, पाली में खबरों एवं विज्ञापन कार्य हेतु प्रतिनिधि की आवश्यकता है।

सम्पर्क करें

बिजनेस रेमेडीज

63/118, क्षीरा पथ, मानसरोवर, जयपुर -302020

0141-3594672, 9929106227

E-Mail: remediesbusiness@gmail.com

businessremedies@yahoo.com

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT. THIS DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR ISSUE TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. THIS PUBLIC ANNOUNCEMENT IS NOT INTENDED FOR PUBLICATION OR DISTRILLITION DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA.



MACOBS TECHNOLOGIES LIMITED

CIN: U74999RJ2019PLC066608

Our Company was originally incorporated as a private limited company under the Companies Act, 2013 in the name and style of "Macobs Technologies Private Limited" bearing Corporate Identification Number U74999RJ2019PTC066608 dated October 14, 2019 issued by the Registrar of Companies, Rajasthan. Subsequently, the name of our Company was changed to "Macobs Technologies Limited" and a fresh Certificate of Incorporation dated August 07, 2023 was issued by the Registrar of Companies, Rajasthan. As on date of this Red Herring Prospectus, the Corporate Identification Number of our Company is U74999RJ2019PLC066608.

Registered Office: Plot No. A-305, Backside National Handloom Corp, Vaishali Nagar, Jaipur, Rajasthan, India-302021

Contact Person: Ankita Soni, Company Secretary & Compliance Officer; Tel No: +91 8062195170 Email: compliance@macobstech.com; Website: www.macobstech.com

THE PROMOTERS OF OUR COMPANY ARE (I) SHIVAM BHATEJA (II) DUSHYANT GANDOTRA (III) DIVYA GANDOTRA

"THE ISSUE IS BEING MADE IN ACCORDANCE WITH CHAPTER IX OF THE SEBI ICDR REGULATIONS (IPO OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES) AND THE EQUITY SHARES ARE PROPOSED TO BE LISTED ON SME PLATFORM OF NSE (NSE EMERGE)."

THE ISSUE

THE ISSUE COMPRISE OF A PUBLIC ISSUE OF 25,95,200 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF Rs. 10/- EACH FULLY PAID (THE "EQUITY SHARES OF MARKETMAKER AND NET ISSUE AND %") FOR CASH AT A PRICE OF Rs/- PER EQUITY SHARES (INCLUDING A PREMIUM OF [.] /- PER EQUITY SHARE) AGGREGATING TO [.] /- LAKHS ("THE ISSUE") BY OUR COMPANY. THE ISSUE COMPRISES A RESERVATION OF WHICH [.] EQUITY SHARES OF Rs. 10/- EACH WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER RESERVATIONS PORTION AND A NET ISSUE TO THE PUBLIC OF [.] EQUITY SHARES OF Rs.10/- EACH IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE NET ISSUE. THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE [.] AND [.] RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF THE COMPANY.

ALLOCATION OF THE ISSUE

- QIB PORTION : 7,39,200 EQUITY SHARES OR 30.00% OF THE NET ISSUE
- RETAIL PORTION : 8,62,400 EQUITY SHARES OR 35.00% OF THE NET ISSUE
- NON-INSTITUTIONAL PORTION : 8,62,400 EQUITY SHARES OR 35.00% OF THE NET ISSUE
- MARKET MAKER PORTION : 1,13,200 EQUITY SHARES OR 5.06% OF THE ISSUE

PRICE BAND : ₹ 71/- to ₹ 75/- PER EQUITY SHARE

THE FLOOR PRICE IS 7.1 TIMES THE FACE VALUE AND CAP PRICE IS 7.5 TIMES OF THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. BIDS CAN BE MADE FOR A MINIMUM OF 1,600 EQUITY SHARES AND IN MULTIPLES OF 1,600 EQUITY SHARES THEREAFTER. THIS ISSUE IS MADE THROUGH BOOK BUILDING PROCESS, IN TERMS OF CHAPTER IX OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018 (THE "SEBI (ICDR) REGULATIONS"), AS AMENDED READ WITH RULE 19(2)(B) OF SECURITIES CONTRACT (REGULATION) RULES, 1957, AS AMENDED.

ISSUE PROGRAM

ANCHOR BID OPENS ON MONDAY, JULY 15, 2024

OPENS ON : TUESDAY, JULY 16, 2024 | CLOSES ON : FRIDAY, JULY 19, 2024

ASBA *	Simple, Safe, Smart way of Application- Make us of it!!!!	*Application supported by blocked amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account, investors can avail the same. For further details check the section on ASBA below.	Mandatory in public issues from January 01, 2016. No cheque will be accepted		Now mandatory in ASBA for Retail Investors applying through Registered Brokers, DPs & RTAs. Retail Investors also have the options to submit the application directly to the ASBA Bank (SCSBs) or to use the facility of linked online trading, demat and bank account. ** Investors are required to ensure that the Bank Account used for applying in linked in their PAN
---------------	---	---	--	--	--

*ASBA has to be availed by all the investors except anchor investors (if any), may be availed by RIs.

For details on ASBA and UPI process, please refer to the details given in ASBA form and abridged prospectus and also please refer to the section "Issue Procedure" beginning on page 181 of the Red Herring Prospectus. The process is also available on the website of SEBI and Stock Exchanges in the General information Document. ASBA forms can be downloaded from the website of Emerge platform of NSE ("NSE Emerge" or Stock Exchange) and can be obtained from the list of banks that is displaying on the website of SEBI at www.sebi.gov.in.

**List of banks supporting UPI is also available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in. For the list of UPI Apps and Banks live on IPO, please refer to the link, www.sebi.gov.in. ICICI Bank Limited has been appointed as Sponsor Bank for the Issue in accordance with the requirements of the SEBI Circular dated November 1, 2018, as amended.

RISKS TO INVESTORS

- Our Equity Shares have never been publicly traded and may experience price and volume fluctuations following the completion of the Issue. Further, our Equity Shares may not result in an active or liquid market and the price of our Equity Shares may be volatile and you may be unable to resell your Equity Shares at or above the Issue Price or at all.
- The Merchant Banker associated with the Issue has not handled any public issues in the past three years.
- The average cost of acquisition of Equity Shares by our Promoters is as follows:

Sr. No.	Name of Promoters and Selling Shareholders	No. of Shares held	Average cost of Acquisition (in ₹)
1	Dushyant Gandotra	23,38,560	7.19
2	Shivam Bhateja	23,38,560	7.19
3	Divya Gandotra	720	7.19

Weighted average cost of acquisition:

Types of transactions	Weighted average cost of acquisition (₹ per Equity Shares)
Weighted average cost of acquisition of primary / new issue of shares.	7.19
Weighted average cost of acquisition for secondary sale / acquisition of shares.	10.00

BASIS FOR ISSUE PRICE

The Price Band and Issue Price has been determined by our Company in consultation with Book Running Lead Manager on the basis of the key business strengths of our Company. The face value of the Equity Shares is Rs. 10/- each and the Issue Price is 7.1 times of the face value at the lower end of the Price Band and 7.5 times of the face value at the upper end of the Price Band.

QUALITATIVE FACTORS

- Strong partnerships, alliances and affiliations with nodal agencies in the area of E-commerce;
- Robust systems and processes across all functions of the company;
- Strong technology backbone supported by a dedicated team of experienced professionals;
- Favourable macro environment;

For a detailed discussion on the qualitative factors which form the basis for computing the price, please refer to sections titled "Our Business" beginning on page 94 of the Red Herring Prospectus.

QUANTITATIVE FACTORS

Information presented below is derived from our Company's Restated Financial Statements prepared in accordance with Indian GAAP. Some of the quantitative factors, which form the basis for computing the price, are as follows:

1. Basic and Diluted Earnings/ (Loss) Per Share ("EPS"), as adjusted for changes in capital as per Restated Financial Statements.

Sr. No.	Particulars	Basic & Diluted EPS (in Rs.)	Weights
1	2023-24	4.43	3
2	2022-23	4.10	2
3	2021-22	0.78	1
4	Weighted Average EPS (Rs.)	3.71	6

2. Price Earnings Ratio ("P/E") in relation to Price Band of Rs. 71/- to Rs. 75/- per Equity Share

Particulars	(P/E) Ratio at the Floor Price (no. of times)	(P/E) Ratio at the Cap Price (no. of times)
Based on Restated Financial Statements		
P/E ratio based on the Basic & Diluted EPS, as restated for FY 2023-24	16.03	16.93
P/E ratio based on the Weighted Average Basic & Diluted EPS	19.14	20.22

3. Industry P/E Ratio

Particulars	P/E Ratio
Highest	1518
Lowest	143
Industry Composite	36.44

4. Return on Net worth (RoNW)

As per Restated Financial Statements

Particulars	RoNW(%)	Weights
2023-24	22.52	3
2022-23	83.64	2
2021-22	97.23	1
Weighted Average EPS (Rs.)	55.35	6

Note : Return on Net Worth (%) = Profit for the period/ year / Net Worth at the end of the period/year.

5. Net Asset Value (NAV)

As per Restated Financial Statements

Financial Year	NAV (₹)
2023-24	13.65
2022-23	3.40
2021-22	0.56
Net Asset Value per Equity Share after the Offer at Floor Price	28.84
Net Asset Value per Equity Share after the Offer at Cap Price	29.90

Notes : Net Asset Value per Equity Share (in Rs.) = Net Worth at the end of the period/year / Weighted number of equity shares outstanding at the end of the period/year.

6. Comparison of accounting ratios with listed industry peers

Name	Current Price	Market Capitalization	Revenue	Profit after Tax	EBITDA	EBITDA Margin (in %)	Price to Earning	Debt	ROCE (in %)	ROE (in %)
Macobs Technologies Limited	(.)	(.)	20.62	2.21	3.41	16.55%	(.)	2.50	30.53%	36.06%
FSN E-Commerce Ventures Ltd	172.99	48972	6386	32.3	376	5.89%	1518	969	6.84%	2.44%
Honasa Consumer Ltd	502.00	15776	1764	121	187.9	10.65%	143	110	17.7%	13.8%

Source : www.bseindia.com, www.nseindia.com.

Notes :

- The figures for our company are based on Restated Financial Statements for the year ended March 31, 2024 after considering the bonus issue.
- P/E Ratio has been computed based on their respective closing market price on July 04, 2024, as divided by the Basic EPS as on March 31, 2024.
- Restated Profit for the year attributable to equity shareholders divided by Net Worth of our Company.
- Net asset value per equity share is calculated as net worth as of the end of relevant year divided by the actual average number of equities shares outstanding at the end of the year.
- Price Earning (P/E) Ratio in relation to the Issue Price of [.] per share.
The face value of our share is Rs. 10/- per share and the floor price is 7.1 times the face value and cap price is 7.5 times of the face value of the equity shares.
Investor should read the above-mentioned information along with the section titled "Risk Factors" beginning on page 27 of the Red Herring Prospectus and the financials of our Company including important profitability and return ratios, as set out in the chapter titled "Restated Financial Information" beginning on page 140 of the Red Herring Prospectus.

7. Key Performance Indicators ("KPIs")

Key Financial & Operational Performance Indicators (KPIs)

(Amount in ₹ Lakhs)

Key Financial Performance	Fiscal 2023-24	Fiscal 2022-23	Fiscal 2021-22
Revenue from operations	2061.79	1478.08	601.29
EBITDA	341.25	285.62	56.37
EBITDA Margin (%)	16.55%	19.32%	9.38%
PAT	221.27	204.5	38.89
PAT Margin (%)	10.73%	13.84%	6.47%
ROE (%)	36.06%	143.76%	189.23%
ROCE (%)	30.53%	106.02%	96.30%

Notes:

- Revenue from operations is the total revenue generated by our Company from the sale of products.
- EBITDA is calculated as Profit before tax + Depreciation & Amortization + Interest Expenses
- EBITDA Margin' is calculated as EBITDA divided by Revenue from Operations
- PAT is calculated as Profit before tax – Tax Expenses
- PAT Margin is calculated as PAT for the period/year divided by Revenue from Operations.
- Return on Equity is ratio of Profit after Tax and Average Shareholder Equity
- Return on Capital Employed is calculated as EBIT divided by capital employed, which is defined as shareholders' equity plus total borrowings {current & non-current}.

Explanation for KPI metrics

KPI	Description
Revenue from operations	Revenue from Operations is used by our management to track the revenue profile of the business and in turn helps to assess the overall financial performance of our Company and volume of our business
EBITDA	EBITDA provides information regarding the operational efficiency of the business
EBITDA Margin	EBITDA Margin (%) is an indicator of the operational profitability and financial performance of our business
PAT	Profit after tax provides information regarding the overall profitability of the business.
PAT Margin	PAT Margin (%) is an indicator of the overall profitability and financial performance of our business.
ROE(%)	RoE provides how efficiently our Company generates profits from shareholders' funds.
ROCE(%)	ROCE provides how efficiently our Company generates earnings from the capital employed in the business.

Key Financial & Operational Performance Indicators (KPIs) in comparison to industry peers (in Crores unless Stated Otherwise)

Key Performance Indicator	FSN E-Commerce Ventures Ltd			Honasa Consumer Ltd		
	Fiscal 2021-22	Fiscal 2022-23	Fiscal 2023-24	Fiscal 2021-22	Fiscal 2022-23	Fiscal 2023-24
Revenue from operations	3773.94	5143.8	6385.63	931.76	1394.8	1919.90

Key Performance Indicator	FSN E-Commerce Ventures Ltd			Honasa Consumer Ltd		
	Fiscal 2021-22	Fiscal 2022-23	Fiscal 2023-24	Fiscal 2021-22	Fiscal 2022-23	Fiscal 2023-24
EBITDA	164.05	257.06	376.09	15.62	44.66	186.79
EBITDA Margin	4.35%	5.00%	5.89%	1.68%	3.20%	9.73%
PAT	41.08	19.26	39.75	19.87	-120.56	110.53
PAT Margin	1.09%	0.37%	0.62%	2.13%	-8.64%	5.76%
ROE(%)	3.07%	1.40%	3.01%	2.79%	-19.23%	12.99%
ROCE(%)	6.87%	5.55%	7.82%	-	-15.23%	14.26%

8. Justification for Basis for Issue price

- Price per share of our Company based on the primary issue of Shares

Other than as mentioned below, there has been no issuance of Equity Shares during the three years preceding the date of this Red Herring Prospectus, where such issuance is equal to or more than 5% of the fully diluted paid-up share capital of the company (calculated based on the pre-issue capital before such transaction(s)), in a single transaction or multiple transactions combined together over a span of 30 days, Except as below:

Date of Allotment	No. of Equity Share Allotted	Face Value (INR)	Issue Price (INR)	Nature of Consideration	Nature of Allotment
04-07-2023	1000000	10	10	Cash	Right
21-07-2023	2020000	10	0	Other than Cash	Bonus
11-10-2023	2970000	10	10	Cash	Right
02-11-2023	1200000	10	10	Cash	Right

Weight Average Cost of Acquisition	7.19
------------------------------------	------

For further details, see "Capital Structure" on page 54 of this Red Herring Prospectus.

b) Price per share of our Company based on the secondary sale / acquisition of Shares

There have no been secondary sale /acquisitions of Equity Shares, where the Promoters and the members of the Promoter Group of the Company are a party to the transaction (excluding gifts), during the Three years preceding the date of this Red Herring Prospectus, where either acquisition or sale is equal to or more than 5% of the fully diluted paid up share capital of the Company (calculated based on the pre-issue capital before such transaction/s), in a single transaction or multiple transactions combined together over a span of rolling 30 days, Except as below:

Date of Transaction	No. of Equity Share Transacted	Face Value (INR)	Transfer Price (INR)	Buyer	Seller
January 9, 2023	1750	10	10	Raman Talwar	Shivam Bhateja
January 9, 2023	1750	10	10	Raman Talwar	Dushyant Gadotra

Weight Average Cost of Acquisition	10
------------------------------------	----

c) Weighted average cost of acquisition, Issue Price

Weighted average cost of acquisition of Equity Shares based on primary/secondary transaction(s), as disclosed in paragraph above, are set out below:

Types of Transactions	Weighted average cost of acquisition (Rs. Per Equity Share)	Cap Price (i.e. Rs. 75/-)	Floor Price (i.e. Rs.71/-)
Weighted average cost of acquisition of primary/new issue as per paragraph a above.	7.19	9.87	10.43
Weighted average cost of acquisition for secondary sale/ acquisition as per paragraph b above.	10	7.1	7.5

Investors should read the above-mentioned information along with section titled "Our Business", "Risk Factors" and "Restated Financial Information" beginning on page 94, 20 and 140 respectively including important profitability and return ratios, as set out in chapter titled "Other Financial Information" on page 141 of the Red Herring Prospectus to have a more informed view.

FOR FURTHER DETAILS, SEE "BASIS FOR ISSUE PRICE" ON PAGE 79 OF THE RHP

Our Company in consultation with the BRLM may consider participation by Anchor Investors. The Anchor Investor Bidding Date shall be one Working Day prior to the Bid/Issue Opening Date in accordance with the SEBI (ICDR) Regulations, 2018. In case of any revisions in the Price Band, the Bid/ Issue Period will be extended by at least three additional Working Days after such revision of the Price Band, subject to the Bid/ Issue Period not exceeding Ten Working Days. In cases of force majeure, banking strike or similar circumstances, our Company may, for reasons to be recorded in writing, extend the Bid/ Issue Period for a minimum of One Working Days, subject to the Bid/ Issue Period not exceeding 10 Working Days. Any revision in the Price Band and the revised Bid/ Issue Period, if applicable, will be widely disseminated by notification to the Stock Exchange, by issuing a press release, and also by indicating the change on the website of the Book Running Lead Manager and the terminals of the other members of the Syndicate and by intimation to SCSBS, the Sponsor Bank, Registered Brokers, Collecting Depository Participants and Registrar and Share Transfer Agents.

The Issue is being made through the Book Building Process, in terms of Rule 19(2)(b)(1) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended ("SCRR") read with Regulation 229 (1) and 253 of the SEBI ICDR Regulations, the Issue is being made for at least 25% of the post Issue paid up equity share capital of our company. The Issue is being made through the book building process wherein not more than 30% of the Net Issue shall be available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("QIBS") (the "QIB Portion"), provided that our Company and Selling Shareholders in consultation with the BRLM may allocate up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis (the "Anchor Investor Portion"). One-third of the Anchor Investor Portion shall be reserved for domestic Mutual Funds, subject to valid Bids being received from the domestic Mutual Funds at or above the Anchor Investor

(Continued next page...)

(Continued from previous page...)

Allocation Price. In the event of under-subscription or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance equity shares shall be added to the QIB Category. 5% of the QIB Portion (excluding the Anchor Investor Portion) shall be available for allocation on a proportionate basis to Mutual Funds only, and the remainder of the QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIB Bidders (other than Anchor Investors), including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. However, if the aggregate demand from Mutual Funds is less than 5% of the QIB Portion (excluding Anchor Investor Portion), the balance Equity Shares available for allocation in the Mutual Fund Portion will be added to the remaining QIB Portion for proportionate allocation to QIBS. Further, not less than 35% of the Net Issue shall be available for allocation on a proportionate basis to Non-Institutional Bidders and not less than 35% of the Net Issue shall be available for allocation to Retail Individual Investors in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received from them at or above the Issue Price. All potential Bidders (except Anchor Investors) are required to mandatorily utilize the Application Supported by Blocked Amount (ASBA*) process providing details of their respective bank account (including UPI ID for RIBS using UPI Mechanism), in which the corresponding Bid Amounts will be blocked by the SCSBs or the Sponsor Bank as applicable. Anchor Investors are not permitted to participate in the Issue through the ASBA process. For details, see "Issue Procedure" on page 181 of the Red Herring Prospectus.

Bidders/Applicants should note that on the basis of PAN, DP ID and Client ID as provided in the Bid cum Application Form, the Bidders/Applicants may be deemed to have authorized the Depositories to provide to the Registrar to the Issue, any requested Demographic Details of the Bidders/Applicants as available on the records of the depositories. These Demographic Details may be used, among other things, for or unblocking of ASBA Account or for other correspondence(s) related to an Issue. Bidders/Applicants are advised to update any changes to their Demographic Details as available in the records of the Depository Participant to ensure accuracy of records. Any delay resulting from failure to update the Demographic Details would be at the Applicants' sole risk. Bidders /Applicants should ensure that PAN, DP ID and the Client ID are correctly filled in the Bid cum Application Form. The PAN, DP ID and Client ID provided in the Bid cum Application Form should match with the PAN, DP ID and Client ID available in the Depository database, otherwise, the Bid cum Application Form is liable to be rejected. Bidders/Applicants should ensure that the beneficiary account provided in the Bid cum Application Form is active.

CONTENTS OF THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY AS REGARDS ITS OBJECTS: For information on the main objects and other objects of our Company, see "Our History and Corporate Structure" on page 118 of the Red Herring Prospectus and Clause III of the Memorandum of Association of our Company. The Memorandum of Association of our Company is a material document for inspection in relation to the Issue. For further details, see the section "Material Contracts and Documents for Inspection" on page 218 of the Red Herring Prospectus.

LIABILITY OF MEMBERS AS PER MOA: The Liability of the members of the Company is Limited.

AMOUNT OF SHARE CAPITAL OF THE COMPANY AND CAPITAL STRUCTURE: The Authorised share capital of the Company is Rs. 1000.00 Lakhs divided into 1,00,00,000 Equity Shares of Rs. 10/- each. The offered, subscribed and paid-up share capital of the Company before the Issue is Rs. 720.00 Lakhs divided into 72,00,000 Equity Shares of Rs. 10/- each. For details of the Capital Structure, see "Capital Structure" on the page 54 of the Red Herring Prospectus.

NAMES OF THE SIGNATORIES TO THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY AND THE NUMBER OF EQUITY SHARES SUBSCRIBED BY THEM:

ORIGINAL SIGNATORIES		
Name of Promoters	Face Value (₹)	No. of Shares
Shivam Bhateja	10	5000
Dushyant Gandotra	10	5000

Details of the main objects of the Company as contained in the Memorandum of Association, see "Our History and Corporate Structure" on page 118 of the Red Herring Prospectus. For details of the share capital and capital structure of the Company see "Capital Structure" on page 54 of the Red Herring Prospectus.

LISTING : The Equity Shares offered through the Red Herring Prospectus are proposed to be listed on the SME Platform of NSE ("NSE EMERGE"). Our Company has received an "in-principle" approval from the NSE for the listing of the Equity Shares pursuant to letter dated April 23, 2024. For the purposes of the Issue, the Designated Stock Exchange shall be NSE. A signed copy of the Red Herring Prospectus has been delivered for registration to the ROC on July 08, 2024 and Prospectus shall be delivered for filing to the RoC in accordance with Section 26(4) of the Companies Act, 2013. For details of the material contracts and documents available for inspection from the date of the Red Herring Prospectus up to the Bid/ Issue Closing Date, see "Material Contracts and Documents for Inspection" on page 218 of the Red Herring Prospectus.

DISCLAIMER CLAUSE OF SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA ("SEBI") : Since the Issue is being made in terms of Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, the Red Herring Prospectus has been filed with SEBI. In terms of the SEBI Regulations, the SEBI shall not issue any observation on the Issue Document. Hence there is no such specific disclaimer clause of SEBI. However, investors may refer to the entire Disclaimer Clause of SEBI beginning on page 164 of the Red Herring Prospectus.

DISCLAIMER CLAUSE OF NSE (THE DESIGNATED STOCK EXCHANGE) : "It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in any way be deemed or construed that the Issue Document has been cleared or approved by NSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Issue Document. The investors are advised to refer to the Issue Document for the full text of the "Disclaimer Clause of NSE" beginning on page 165 of the Red Herring Prospectus.

GENERAL RISK : Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this Issue unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in this Issue. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of the Issue or and this Issue, including the risks involved. The Equity Shares have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the Red Herring Prospectus. Specific attention of the investors is invited to "Risk Factors" on page 20 of the Red Herring Prospectus.

BOOK RUNNING LEAD MANAGER TO THE ISSUE	REGISTRAR TO THE ISSUE
SKI CAPITAL SERVICES LIMITED SEBI Registration No.: INM000012768 Address: 718, Dr Joshi Road, Karol Bagh, New Delhi- 110005 Telephone No.: +91-011-411189899 Email: mtliipo@skicapital.net Website: https://www.skicapital.net/ Contact Person Name: Mr. Ghanisht Nagpal	MAASHITLA SECURITIES PRIVATE LIMITED SEBI Registration No.: INR000004370 Address : 451, Krishna Apra Business Square, Netaji Subhash Place, Pitampura, Delhi-110034 Tel No: + 91 -11-4512-1795; Email: investor.ipo@maashitla.com Website: https://www.maashitla.com/ Contact Person: Mr. Mukul Agrawal

COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER	
Ankita Soni Plot No. A-305,Backside National Handloom Corp. Vaishali Nagar,Jaipur,Rajasthan,India,302021. Tel: 8062195170; E-mail: compliance@macobstech.com	

Investors can contact the Compliance Officer or the Registrar to the Issue in case of any pre-Issue or post-Issue related problems, such as non-receipt of letters of allotment, credit of allotted shares in the respective beneficiary account, etc.

Availability of Red Herring Prospectus : Investors are advised to refer to the Red Herring Prospectus and the Risk Factors contained therein, before applying in the offer. Full copy of the Red Herring Prospectus will be available at the website of SEBI at www.sebi.gov.in; the website of Stock Exchange at www.nseindia.com, the website of BRLM at www.skicapital.net and website of Company at www.macobstech.com

Availability of Bid-Cum-Application forms : Bid-Cum-Application forms can be obtained from the Company: Macobs Technologies Limited, Book Running Lead Manager; Shreni Shares Limited. Application Forms can also be obtained from the Stock Exchange and list of SCSBS available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in and website of Stock Exchange at www.nseindia.com.

Application Supported by Blocked Amount (ASBA) : All investors in this offer have to compulsorily apply through ASBA. The investors are required to fill the ASBA form and submit the same to their banks. The SCSB will block the amount in the account as per the authority contained in ASBA form. On allotment, amount will be unblocked and account will be debited only to the extent required to be paid for allotment of shares. Hence, there will be no need of refund.

For more details on the offer process and how to apply, please refer to the details given in application forms and abridged prospectus and also please refer to the chapter "Issue Procedure" on page 181 of the Red Herring Prospectus.

BANKER TO THE ISSUE: ICICI Bank Limited

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the RHP

Date: Place:	For Macobs Technologies Limited
	Sd/-
	Dushyant Gandotra
	Designation : Managing Director DIN : 08360731

Macobs Technologies Limited is proposing, subject to market conditions and other considerations, to make its initial public offer of its Equity Shares and has filed the Red Herring Prospectus with the Registrar of Companies, Jaipur Rajasthan on July 08, 2024. The Red Herring Prospectus is available on the website of the Book Running Lead Manager at www.skicapital.net, the website of the NSE i.e., www.nseindia.com, and website of our Company at www.macobstech.com

Investor should note that investment in equity shares involves a high degree of risk. For details, investors should refer to and rely on the Red Herring Prospectus, including the section titled "Risk Factors" of the Red Herring Prospectus, which has been filed with ROC. The Equity Shares have not been and will not be registered under the US Securities Act ("the Securities Act") or any state securities laws in United States and may not be offered or sold within the United States or to, or for the account or benefit of, "U.S. persons" (as defined in Regulations under the securities Act), except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act of 1933.

BR

सम्पादकीय

राज्य बजट घोषणाएं

कितनी होगी क्रियान्वित?

भजनलाल सरकार ने राजस्थान का गत दिवस बुधवार को विधानसभा में अपना पहला पूर्ण बजट पेश कर दिया है। राजस्थान की डिप्टी सीएम एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने अपने करीब तीन घंटे के बजट भाषण में मरुधरा के विकास के लिए भजनलाल सरकार के विजन को सामने रखा। इसमें कई बड़ी और अहम घोषणाएं की हैं। अब देखना होगा कि राज्य बजट में की गई घोषणाएं कितनी क्रियान्वित होगी? यह भविष्य के गत में है। बजट में कुछ हद तक युवा वर्ग पर भी फोकस किया गया है। इसके तहत सरकारी नौकरियों को बड़ा तोहफा भी दिया है। दिया कुमारी ने अगले पांच वर्ष में चार लाख नई नौकरियां देने का ऐलान किया है। सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशनर्स की इलाज राशि 30 हजार से बढ़ाकर 50 हजार कर दी है। वहीं वित्त मंत्री ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जोर देते हुए 500 नई रोडवेज बसें खरीदे जाने का भी ऐलान किया है। वहीं जन-जन के आस्था केंद्र खाटूश्यामजी में विकास के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का ऐलान किया है। पांच साल में चार लाख नौकरियां दिए जाने का ऐलान के तहत एक लाख नौकरियां पहले साल में दिए जाने की घोषणा तो कर दी है, लेकिन ऐसा संभव नहीं लगता है। सात महीने पहले सत्ता में आई बीजेपी की भजनलाल सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट तो पेश कर दिया है, पर इसमें की गई घोषणाएं कब तक पूरी होगी इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया है। वैसे तो बजट से युवाओं, महिलाओं, किसानों और कर्मचारियों समेत सभी वर्गों का पूरा ध्यान रखा गया है। सबसे ज्यादा युवाओं को बजट का इंतजार है। उन्हें नई सरकार से बड़ी संख्या में सरकारी नौकरियों की आस है। विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने बेरोजगार युवाओं, किसानों और महिला विकास को लेकर बड़े वादे किए थे। इन्हीं वादों के दम पर वह कांग्रेस से सत्ता छिनने में सफल हो पाई थी। करीब दस साल के बाद राजस्थान में सीएम के अलावा उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री ने बजट पेश किया। इससे पहले राजस्थान में वित्त मंत्रालय सीएम के पास ही हुआ करता था। लिहाजा वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत अपनी सरकारों में खुद बजट पेश करते थे। अब दस साल बाद डिप्टी सीएम बजट पेश किया।

BR

सूचना

इस पृष्ठ पर प्रकाशित सभी विशेष लेख व्यक्तिगत सोच के आधार पर है।
-संपादक

पतंजलि ने कोर्ट को 16 मई के हलफनामे में बताया था कि समूह ने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से संबंधित विज्ञापन हटाने के लिए उठाए कदम

अब पतंजलि कोर्ट को फिर बतायेगा कि क्या 14 उत्पादों के विज्ञापन हटा लिए गए



बिजनेस रेमेडीज/नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने योगगुरु रामदेव के पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को मंगलवार को एक हलफनामा दाखिल करने को कहा, जिसमें यह बताया जाए कि उन 14 उत्पादों के विज्ञापन वापस लिए गए हैं या नहीं, जिनके विनिर्माण लाइसेंस शुरू में निलंबित किए गए थे और बाद में बहाल कर दिए गए।

उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने 15 अप्रैल को एक आदेश जारी कर पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड और दिव्य फार्मसी के 14 उत्पादों के

विनिर्माण लाइसेंस निलंबित कर दिए थे।

राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने एक ताजा घटनाक्रम में उच्चतम न्यायालय में एक हलफनामा दायर कर कहा है कि विवाद के मदेनजर पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की शिकायतों की जांच करने वाली एक उच्चस्तरीय समिति की रिपोर्ट के बाद निलंबन आदेश रद्द कर दिया गया है। उसने 17 मई को कहा कि 15 अप्रैल के आदेश पर अमल को रोक दिया गया और बाद में निलंबन आदेश रद्द कर दिया गया। हालांकि, सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने पतंजलि के 16 मई के हलफनामे का संज्ञान लिया, जिसमें कंपनी ने कहा था कि 15 अप्रैल के निलंबन आदेश के मदेनजर उक्त 14

उत्पादों की बिक्री रोक दी गई है।

हलफनामे में कहा गया कि कंपनी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से संबंधित विज्ञापन हटाने के लिए भी कदम उठाए हैं।

श्रीष अदालत भारतीय चिकित्सा संघ (आईएमए) की ओर से दायर उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पतंजलि पर कोविड टीकाकरण अभियान और आधुनिक चिकित्सा प्रणालियों के खिलाफ दुष्प्रचार अभियान चलाने का आरोप लगाया गया। पीठ ने आईएमए की ओर से पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्त । पीएस पटवालिया से पूछा कि क्या उन्होंने जरूरी तत्परता दिखाई है और पता लगाया है कि मई में पतंजलि द्वारा हलफनामा दाखिल किए जाने के बाद ये विज्ञापन हटाए गए या नहीं।

सुनवाई के दौरान एक आवेदक के वकील ने कहा कि केंद्र को भ्रामक विज्ञापनों से जुड़े मामले को यथासंभव जल्द से जल्द देखना चाहिए। उन्होंने कहा, “इसका ऑनलाइन उद्योग पर बहुत असर पड़ रहा है।”

न्यायमूर्ति कोहली ने कहा, “किसी को परेशानी पहुंचाने की कोई मंशा नहीं है। मंशा केवल विशेष क्षेत्रों और विशेष पहलुओं पर ध्यान देने की है।” पीठ ने केंद्र की ओर से पक्ष रख रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज से कहा, “क्या हम आपसे एक बैठक बुलाने का अनुरोध कर सकते हैं, ताकि सभी हितधारकों और आपके विभाग के वरिष्ठतम अधिकारियों के बीच विचार-विमर्श हो सके?” उन्होंने कहा कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने विभिन्न

हितधारकों के साथ उच्चस्तरीय बैठकों की हैं, ताकि उनके व्यक्त सुझां और कठिनाइयों का समाधान किया जा सके। पीठ ने मामले की सुनवाई के लिए 30 जुलाई की तारीख तय की।

श्रीष अदालत ने भ्रामक विज्ञापन मामले में योग गुरु रामदेव, उनके सहयोगी बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को जारी अवमानना नोटिस पर 14 मई को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने पिछले साल 21 नवंबर को श्रीष अदालत को आश्वासन दिया था कि वह किसी भी कानून का, विशेष रूप से उसके द्वारा निर्मित और विपणन किए जाने वाले उत्पादों के विज्ञापन या ब्रांडिंग से संबंधित कानून का उल्लंघन नहीं करेगा।

यमुना अथॉरिटी ने आवासीय प्लॉटों की स्कीम लॉन्च की

नोएडा एयरपोर्ट और फिल्म सिटी के पास प्लॉट खरीदने का मौका



यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

राशि का पेमेंट करें और आपका आवेदन हो जाएगा।

बढ़ सकती है प्लॉट की संख्या : अथॉरिटी के अधिकारियों का कहना है कि इस स्कीम में आवासीय प्लॉटों की संख्या आगे बढ़ाई भी जा सकती है। यानि कि जो लोग इस स्कीम में आवेदन करेंगे उनके ड्रा के समय 381 से ज्यादा करीब 700 तक प्लॉटों की संख्या हो सकती है। अभी जिन जिन सेक्टरों में प्लॉट बचे हुए हैं उनकी लिस्ट तैयार की जा रही है। ड्रा के समय इन प्लॉटों को भी उसमें शामिल कर दिया जाएगा। मतलब कि कुल मिलाकर प्लॉटों की संख्या बढ़ा जाएगी।

यमुना अथॉरिटी ने अक्टूबर 2023 में लॉन्च की गई आवासीय योजना में करीब 450

2024 को रात 12 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आगामी 20 अगस्त को इसका ड्रा निकाल दिया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि ड्रा अपने निर्धारित समय पर ही होगा। इससे पहले भी यीडा की स्कीमों में ड्रा निर्धारित समय पर हो होता रहा है। इस बारे में विस्तार से जानकारी के लिए आप अथॉरिटी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

आवेदन के समय कितना पैसा देना होगा : इस स्कीम में आवेदन के समय प्लॉट की कुल कीमत की 10 फीसदी राशि ईएमडी (अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट) रखी गई है। यानि आवेदन करते समय आपको प्लॉट की कुल कीमत का 10 प्रतिशत पैसा जमा करना होगा। जिन लोगों का नाम ड्रा में नहीं आया एक महीने के अंदर उनका पैसा यमुना अथॉरिटी उनके अकाउंट में वापस कर देगी।

आवेदन के लिए भी मिलेगा बैंक से लोन : जिनके पास अभी पैसे नहीं हैं, पर वे आवेदन करना चाहते हैं, वह बैंक से लोन लेकर भी ईएमडी राशि जमा कर सकते हैं। खासकर आईसीआईसीआई बैंक इस स्कीम में ईएमडी राशि के लिए लोन उपलब्ध करा रहा है। हो सकता है कि कोई अन्य बैंक भी यह सुविधा दे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित, सम्मान भारत के लोगों को किया समर्पित

बिज़नेस रेमेडीज/मॉस्को/आईएनएस

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंगलवार को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल द फर्स्ट-कॉल’ से सम्मानित किया गया।

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद ग्रेड क्रेमलिन पैलेस में आयोजित एक समारोह के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को देश का सर्वोच्च राजकीय सम्मान प्रदान किया। उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री को रूस और भारत के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी के साथ रूसी और भारतीय लोगों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को विकसित करने में



उत्कृष्ट कार्यों के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। समारोह की शुरुआत में पुतिन ने कहा, कि प्रिय मित्र, आपको ‘ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द फर्स्ट-कॉल’ से सम्मानित करना हमारे देश और यहां के लोगों के बीच मित्रता और आपसी समझ को मजबूत करने में आपके महत्वपूर्ण योगदान के लिए आपके प्रति रूस की कृतज्ञता को दर्शाता है। उन्होंने कहा, कि

आपने हमेशा हमारे देश के साथ संपर्क बढ़ाने की वकालत की है, यहां तक कि जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब भी आपने रूसी क्षेत्रों, इस मामले में आस्ट्राखान क्षेत्र के साथ सिस्टर-सिटी संबंध स्थापित करने की पहल की थी। रूस के राष्ट्रपति ने अपने भाषण में उल्लेख किया कि 10 वर्षों तक भारत के प्रधानमंत्री होने के नाते, आपने वास्तव में यह कोशिश की कि

रूस-भारत संबंधों विशेषकर रणनीतिक साझेदारी बेहतर हो और आपने इसे हासिल कर लिया है। आपके सहयोग से, व्यापार, आर्थिक और सैन्य-तकनीकी क्षेत्रों, परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा, उच्च प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष में सबसे बड़ी रूसी-भारतीय परियोजनाएं सफलतापूर्वक संचारू रूप से चलाई जा रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में रूस-भारत सहयोग के लिए एक स्थिर आधार निर्माण करने में आपके योगदान को कम करके आंकना मुश्किल है।

उल्लेखनीय है कि इस ‘ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द फर्स्ट कॉल’ सम्मान के लिए जो चीजें दी जाती हैं, उसमें एक बैज, एक स्टार, एक ऑर्डर चैन और एक

ऑर्डर रिबन होता है। वहीं, युद्ध क्षेत्र में पराक्रम दिखाने वाले को दिए जाने वाले %ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द फर्स्ट-कॉल% सम्मान के तहत एक बैज और स्टार के साथ तलवारें दी जाती हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस सम्मान को ग्रहण करने के बाद कहा कि ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल प्राप्त करने पर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। मैं इसे भारत के लोगों को समर्पित करता हूं। इस सम्मान की स्थापना जार पीटर-एक ने 1699 के आसपास की थी और यह रूस के सबसे पुराने पुरस्कारों में से एक है। इसे 1918 में समाप्त कर दिया गया था और 1998 में रूस के राष्ट्रपति के आदेश पर फिर से इसे बहाल किया गया था।

खादी ग्रामोद्योग ने वित्त वर्ष 24 में दर्ज की 1.55 लाख करोड़ रुपये की रिकॉर्ड बिक्री

बिज़नेस रेमेडीज/नई दिल्ली/आईएनएस

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने वित्त वर्ष 2023-24 में 15.7 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ 1.55 लाख करोड़ रुपये की बिक्री हासिल की है। इस दौरान ग्रामीण इलाकों में 10.17 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। सरकार की ओर से जारी किए गए आधिकारिक आंकड़ों से यह जानकारी मिली है।

केवीआईसी के चेयरमैन मनोज कुमार ने कहा कि पिछले 10 वर्षों के मोदी सरकार के कार्यकाल में खादी और ग्रामीण इंडस्ट्री के उत्पादों की बिक्री पांच गुना बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़कर 1,55,673.12 करोड़ रुपये हो गई है, जो कि

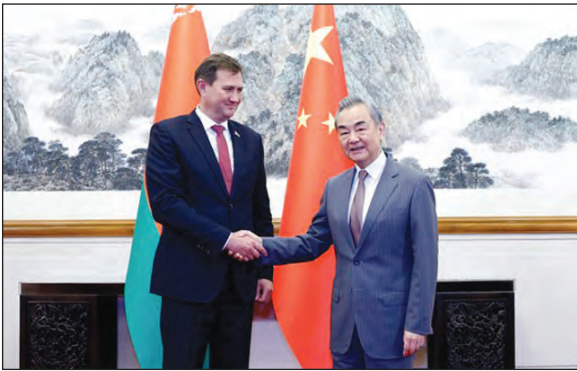
2013-14 में 31,154.2 करोड़ रुपये थी। कुमार ने आगे कहा कि वित्त वर्ष 2013-14 के मुकाबले वित्त वर्ष 2023-24 में बिक्री में 400 प्रतिशत, उत्पादन में 314.79 प्रतिशत, नए रोजगार सृजन में 80.96 प्रतिशत का उछाल दर्ज किया गया है। केवीआईसी का यह योगदान भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और 2047 एक विकसित भारत बनाने में एक अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से खादी को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे लोगों का खादी के उत्पादों पर विश्वास बढ़ा है। आज खादी भारतीय युवाओं के बीच एक नई स्टेटस सिंबल के रूप में उभरा है। खादी और ग्रामीण इंडस्ट्री के उत्पादों की मांग

बाजार में बढ़ रही है, जिसका असर हमारे प्रदर्शन पर भी दिख रहा है। आगे कहा कि पिछले 10 वर्षों में खादी और ग्राम उद्योग के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम मिलने लगे हैं। ये आंकड़े दिखाते हैं कि ‘मेक इन इंडिया’ और ‘वोकल फॉर लोकल’ जैसे अभियानों से स्वदेशी उत्पादों पर लोगों का विश्वास बढ़ा है। पिछले 10 वर्षों में खादी कपड़े के उत्पादन में अप्रत्याशित 295 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2013-14 में खादी कपड़े का उत्पादन 811.08 करोड़ रुपये था, जो वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़कर 3,206 करोड़ रुपये हो गया है। वित्त वर्ष 2022-23 में खादी कपड़े का उत्पादन 2,915 करोड़ रुपये पर था।

चीन के विदेश मंत्री ने बेलारूस को शांगहाई सहयोग संगठन का सदस्य बनने पर बधाई दी

बिज़नेस रेमेडीज/बीजिंग/आईएनएस

चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने पेइचिंग में यात्रा पर आए बेलारूस के विदेश मंत्री मस्किम रिचेंकोव के साथ वार्ता की। वांग यी ने बेलारूस को शांगहाई सहयोग संगठन का सदस्य बनने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि चीन एससीओ के वर्तमान अध्यक्ष देश के नाते विभिन्न पक्षों के साथ शांगहाई भावना का प्रचार कर समन्वय मजबूत कर एससीओ को अधिक व्यावहारिक और मजबूत बनाने को तैयार है ताकि एससीओ की



आवाज अधिक बुलंद हो और शांति, स्थिरता व विकास बढ़ाने में अधिक बड़ी भूमिका निभाई जाए।

मस्किम रिचेंकोव ने कहा कि विदेश मंत्री बनने के बाद

चीन मेरी पहली विदेश यात्रा का गंतव्य है। हम चीन के साथ विभिन्न क्षेत्रों के व्यावहारिक सहयोग का विस्तार करने को उत्सुक हैं। बेलारूस सक्रियता से एससीओ वृहद परिवार की

विभिन्न गतिविधियों में भाग लेगा। दोनों पक्षों के समान विचार हैं कि वे पारस्परिक विश्वसनीय दोस्त बने रहेंगे। वे वैश्विक दक्षिण देशों की एकता व समन्वय मजबूत कर एक साथ विकासशील देशों के जायज हितों की सुरक्षा करेंगे। दोनों पक्षों ने यूक्रेन संकट पर रायों का आदान-प्रदान भी किया। वांग यी ने कहा कि वर्तमान में फौरन कार्य मैदान के बाहर युद्ध न फैलने, युद्ध न बढ़ने और विभिन्न पक्षों का उकसावा नहीं देने के तीन सिद्धांतों का पालन करना है। चीन रचनात्मक भूमिका जारी रखेगा।

चीन के केंद्रीय सैन्य आयोग ने मानद उपाधि पुरस्कार समारोह आयोजित किया

बिज़नेस रेमेडीज/बीजिंग/आईएनएस

चीनी जन मुक्ति सेना की स्थापना की 97वीं वर्षगांठ के अवसर पर, चीनी केंद्रीय सैन्य आयोग ने मंगलवार को पेइचिंग में एक भव्य मानद उपाधि पुरस्कार समारोह आयोजित किया। सीपीसी केंद्रीय समिति के महासचिव, चीनी राष्ट्रपति और केंद्रीय सैन्य आयोग के अध्यक्ष शी चिनफिंग ने मानद उपाधि प्राप्त करने वाली इकाइयों को ध्वज प्रदान किए।

18 सम्मानित सैनिकों ने कार्यक्रम स्थल में प्रवेश किया और पुरस्कार समारोह शुरू हुआ, जिसमें सभी दर्शकों ने चीन लोक गणराज्य का राष्ट्रागान



गाया। सीपीसी केंद्रीय समिति के पोलित ब्यूरो के सदस्य और केंद्रीय सैन्य आयोग के उपाध्यक्ष हे वेइतोंग ने समारोह की अध्यक्षता की।

शी चिनफिंग ने थल सेना की एक ब्रिगेड की पहली बटालियन की दूसरी कंपनी को ध्वज से सम्मानित किया, जिसने ‘मॉडल रॉकेट आर्टिलरी

कंपनी’ की मानद उपाधि जीती थी। कंपनी के अधिकारियों और सैनिकों के प्रतिनिधियों ने शी चिनफिंग को सलाम किया। शी चिनफिंग ने उन्हें बधाई दी और उनके साथ ग्रुप फोटो ली। चीनी केंद्रीय सैन्य आयोग का जनरल पद पर पदोन्नति समारोह भी आयोजित किया गया। शी चिनफिंग ने केंद्रीय सैन्य आयोग के राजनीतिक कार्य विभाग के कार्यकारी उप निदेशक हे होंगजुन को जनरल के पद पर पदोन्नत करने का एक आदेश जारी किया और उन्हें बधाई दी। हे होंगजुन ने शी चिनफिंग को सलाम किया और समारोह में भाग लेने वाले सभी साथियों को सलाम किया। इस दौरान दर्शकों ने जोरदार तालियां बजाईं।

बीमा। बैंकिंग। ज्वैलरी

पिरामल एंटरप्राइजेज को वित्त वर्ष 2025 में प्रबंधन के तहत परिसंपत्ति में 15 प्रतिशत वृद्धि की उम्मीद

बिज़नेस रेमेडीज/नई दिल्ली

पिरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने अपनी 77वीं वार्षिक आम बैठक में अपने खुदरा ऋण कारोबार के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया और भविष्य के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए। कंपनी का लक्ष्य साल-दर-साल 15 प्रतिशत की दर से वृद्धि करना और वित्त वर्ष 25 के अंत तक अपने कुल प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियों (एयूएम) को 80,000 करोड़ रुपये तक बढ़ाना है। कंपनी ने वित्त वर्ष 28 तक अपने कुल एयूएम को 1.5 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है।

कंपनी के विविध



पोर्टफोलियो में 70 प्रतिशत खुदरा और 30 प्रतिशत थोक उधार का अनुकूल एयूएम मिश्रण है, जिसमें खुदरा एयूएम जून 2024 में 50,000 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर जाएगा।

कंपनी की योजना अपने खुदरा कारोबार का विस्तार करके कुल बही का 75 प्रतिशत हिस्सा बनाने की है, जबकि शेष 25 प्रतिशत थोक उधार के रूप

में होगा। पिरामल फाइनेंस, पिरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जो किफायती आवास वित्त में अग्रणी है। कंपनी मोर्टगेज ऋण, आवास वित्त और असुरक्षित ऋण सहित कई वित्तीय उत्पाद प्रदान करती है। 1.3 मिलियन सक्रिय ग्राहकों सहित 4.1 मिलियन के मजबूत ग्राहक आधार के साथ, पिरामल फाइनेंस 26 राज्यों और 625

जिलों में 490 पारंपरिक शाखाओं और 194 माइक्रोफाइनेंस शाखाओं के माध्यम से काम करता है, जो देश के मेट्रो-आसन्न क्षेत्रों और टियर 1, 2 और 3 शहरों में 13,000 से अधिक पिन कोडों को सेवा प्रदान करता है।

पिरामल एंटरप्राइजेज के चेयरमैन अजय पिरामल ने बताया कि पिरामल एंटरप्राइजेज डेटा-संचालित होने और प्रौद्योगिकी और एनालिटिक्स का उपयोग करके विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। हम भविष्य के विकास के लिए एक मजबूत आधार बनाने के लिए लोगों, वितरण चैनलों, प्रौद्योगिकी और एनालिटिक्स में भारी निवेश

करते हैं। हमारा खुदरा ऋण व्यवसाय अच्छी तरह से बढ़ रहा है, और हम सुलभ वित्तीय समाधान प्रदान करते हैं जो सरकार के एमएसएमई संवर्धन लक्ष्यों का समर्थन करते हैं।

पिरामल ने कहा कि हम किफायती आवास वित्त में बाजार के अग्रणी हैं, जो बजट ग्राहकों के लिए वित्तीय समाधान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारे विविध उत्पाद पोर्टफोलियो और व्यापक उपस्थिति हमें वित्तीय समावेशन और सरकार के एमएसएमई संवर्धन लक्ष्यों का समर्थन करने में मदद करते हैं। स्थिरता पिरामल एंटरप्राइजेज के व्यावसायिक लोकाचार के मूल में बनी हुई है।

2023-24 में नई नौकरियों की संख्या दोगुनी से अधिक, संख्या 46.6 मिलियन के पार : आरबीआई

बिज़नेस रेमेडीज/नई दिल्ली/आईएनएस

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2023-24 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में 46.6 मिलियन नई नौकरियां पैदा हुईं।

देश में कार्यरत लोगों की कुल संख्या 2022-23 में 596.7 मिलियन से बढ़कर 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष में 643.3 मिलियन हो गई। आंकड़ों से पता चलता है कि जहां 2017-18 से 2021-22 के बीच औसतन 20 मिलियन नौकरियां पैदा हुईं, वहीं 2023-24 के दौरान यह संख्या दोगुनी से अधिक हो गई। आरबीआई के क्लेसमे डेटा बेस में पूंजी, श्रम, ऊर्जा, सामग्री और सेवाएं जैसे उत्पादन के पांच प्रमुख



इनपुट शामिल हैं। इस डेटाबेस को 27 उद्योगों के लिए बनाया गया है, जो कुल मिलाकर छह सेक्टर से तैयार किए गए हैं जो पूरी अर्थव्यवस्था को कवर करते हैं। आरबीआई ने पहली बार उपलब्ध जानकारी के आधार पर वित्त वर्ष 2024 में कुल अर्थव्यवस्था के लिए उत्पादकता का सहज पूर्वानुमान भी लगाया है। यह श्रमिकों के शिक्षा स्तर के आधार पर अर्थव्यवस्था में श्रम की गुणवत्ता को दर्शाता है। डेटा शिक्षा स्तर और आयु समूहों में

रोजगार की वृद्धि को दर्शाता है। वित्त वर्ष 2014 में बेरोजगारी 2.2 प्रतिशत थी जो वित्त वर्ष 2018 में घटकर 1.4 प्रतिशत हो गई है। निर्माण को छोड़कर अब सेवा क्षेत्र में अधिकांश कार्यबल काम कर रहा है यानी कृषि में कार्यरत लोगों से यह धीरे-धीरे बाहर जा रहा है। यह 2000-2011 की अवधि के बिल्कुल उलट है क्योंकि तब निर्माण क्षेत्र कार्यबल को बड़ी संख्या में नौकरियां प्रदान कर रहा था।

‘फिस्कल से जुड़ी समझदारी का इस्तेमाल करना जारी रखेगी सरकार’

बिज़नेस रेमेडीज/नई दिल्ली

हमारा ‘आशावाद’ इस आशा और उम्मीद पर टिका हुआ है कि सरकार फिस्कल से जुड़ी समझदारी का इस्तेमाल करना जारी रखेगी। मुद्रास्फीति की स्थितियों और भू-राजनीतिक संघर्षों के कारण बढ़ती वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच, समझदारी भारी फिस्कल नीतियों के साथ अच्छी तरह से संतुलित एक बजट, देश की विकास गति को बनाए रखने और एक मजबूत और टिकाऊ आर्थिक भविष्य सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है।

हम विनिर्माण क्षेत्र (मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर) को मजबूत बनाने और पूंजीगत



अॉनंद्रेज कुबिक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, होम क्रेडिट इंडिया

व्यय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार की पहलों के आधार पर अहम प्रभावों का अनुमान लगाते हैं, जो भारत के आर्थिक विकास की वक्र रेखा को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे। उद्योग के दृष्टिकोण से, हमारी उम्मीदें यह होंगी कि एनबीएफसी के लिए तरलता-

संवर्धन (लिक्विडिटी-एंग्जान्समेंट) के उपायों को बढ़ाने की दिशा में जरूरी और उपयुक्त कदम उठाने के लिए सरकार की ओर से सहायता मिलेगी।

हमें उम्मीद है कि यह बजट फाइनेंशियल सेक्टर में हो रहे बदलावों को आगे बढ़ाने के लिए डिजिटल बुनियादी ढाँचे और अन्य रूप-रेखा उपायों को तेज करने के साथ-साथ कंज्यूमर-फ्रेडली और आसान बनाई गई नीतियां मुहैया करवाना जारी रखेगा। कुल मिलाकर, हम आशावादी हैं कि यह बजट एक मजबूत, समावेशी और तकनीकी रूप से उन्नत अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हुए, विकास और फिस्कल जिम्मेदारी के बीच सही संतुलन बनाएगा।

टाटा एसेट मैनेजमेंट ने भारत का पहला टूरिजम इंडेक्स फंड लॉन्च किया

बिज़नेस रेमेडीज/मुंबई

म्यूचुअल फंड उद्योग में अग्रणी टाटा एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने देश का पहला टूरिजम इंडेक्स फंड लॉन्च किया है, जिसमें निफ्टी 500 का हिस्सा बनने वाली कुछ कंपनियां शामिल हैं। टाटा निफ्टी इंडिया टूरिजम इंडेक्स फंड निफ्टी इंडिया टूरिजम इंडेक्स (TRI, यानी टोटल रिटर्न इंडेक्स) को ट्रैक करेगा। यह एक ओपन-एंडेड इंडेक्स फंड है। निवेशकों को यात्रा, पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी व्यवसायों में सबसे तेजी से बढ़ती हुई भारत की कंपनियों में निवेश के अवसर देने के लिए इसे सावधानीपूर्वक डिजाइन किया गया है। इंडेक्स में शामिल कंपनियां अपने-अपने क्षेत्रों में अग्रणी हैं और बढ़ती डिस्पोजेबल आय, भारतीय



उपभोक्ता की बदलती पसंद और डिस्क्रिजिनरी खर्चों में हो रही बढ़त से उन्हें काफी लाभ मिल रहे हैं।

इंडेक्स फंड के लॉन्च पर, टाटा एसेट मैनेजमेंट के मुख्य व्यवसाय अधिकारी आनंद वरदराजन ने कहा कि बढ़ी हुई डिस्पोजेबल आय, बुनियादी सुविधाओं में विकास जैसे कि बेहतर हाईवे, कनेक्टिविटी, बेहतर रेलवे सुविधा और गति और नए हवाई अड्डों ने यात्रा को आसान, तेज और सुरक्षित बना दिया है। देशांतर्गत हवाई यात्रा

सुविधाओं, होटल, रेस्तरां और यात्रा में तेजी से वृद्धि हो रही है, जो पर्यटन क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा संकेत है। सभी प्रकार की यात्राएं बढ़ रही हैं, चाहे वह तीर्थयात्रा हो, व्यवसाय, मेडिकल या छुट्टी के लिए हो। इससे पर्यटन एक क्षेत्र के रूप में विकसित हुआ है और इस क्षेत्र के विकास से लाभ उठाने के लिए इसमें निवेश करना और इसे लक्ष्य बनाना आवश्यक है।

टाटा निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स फंड की शुरुआत ऐसे समय में हुई है जब भारतीय

अर्थव्यवस्था मजबूत निवेश और खपत से प्रेरित उल्लेखनीय लचीलापन दिखा रही है। भारत में मध्यम वर्ग का बढ़ना आकांक्षामूलक और अनुभवामूलक यात्रा में वृद्धि ला रहा है, बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश को बढ़ावा मिल रहा है, हवाई मार्ग क्षमताओं का विस्तार हो रहा है, जिससे यात्रा अधिक सुलभ हो गई है। इसके अलावा, प्रौद्योगिकी में उन्नति ने ऑनलाइन रेस्तरां एप्रीगेटर्स और बढ़ती डिजिटली अर्थव्यवस्था के साथ यात्रा और रेस्तरां क्षेत्र में क्रांति लायी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अलग-अलग डेस्टिनेशंस और अनुभवों को प्रदर्शित कर रहे हैं, जिससे यात्रा करने की इच्छा को प्रोत्साहन मिल रहा है। वरदराजन ने कहा कि नतीजतन, भारत का यात्रा और पर्यटन व्यय 2019 में

140 बिलियन से बढ़कर 2030 तक 406 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है (स्रोत-यूरोमॉनीटर, सिस्टमैटिक्स इस्टीमेटेशनल रिसर्च)।

इंडेक्स पद्धति : टाटा निफ्टी इंडिया टूरिजम इंडेक्स फंड में वर्तमान में 17 स्टॉक शामिल हैं (21 जून 2024 तक), इसकी इंडेक्स पद्धति में पर्यटन से संबंधित सभी सेगमेंट्स का इष्टतम प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए कड़े मानदंडों का पालन किया जाता है, इंडेक्स में अधिकतम स्टॉक स्तर की सीमा 20% है। इस इंडेक्स में मूल इंडेक्स निफ्टी 500 से अधिकतम 30 स्टॉक हो सकते हैं। विविधीकरण और जोखिम प्रबंधन पर ध्यान देते हुए, इंडेक्स घटकों को प्री-प्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर भारित किया जाता है।

श्री एम पेपर बोर्ड्स लिमिटेड का रु. 39.83 करोड़ का आईपीओ 12 जुलाई को खुलेगा

कंपनी रु. 67-69 प्रति शेयर के प्राइज बैंड में रु. 10 मूल्य के 57.72 लाख इक्विटी शेयर पेश कर रही है, कंपनी के शेयर बीएसई लिमिटेड (बीएसई एसएसई) के एसएसई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होंगे



बिजनेस रेमेडीज/मुंबई। 3 दशकों से अधिक समय से रिसाइक्ल्ड पेपर-आधारित कोटेड डुप्लेक्स बोर्ड उत्पादों के निर्माण के व्यवसाय में लगी हुई मुंबई स्थित कंपनी श्री एम पेपर बोर्ड्स लिमिटेड अपने एसएसई आईपीओ के माध्यम से रु. 39.83 करोड़ तक जुटाने की योजना बना रही है। पब्लिक इश्यू 12 जुलाई को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और 16 जुलाई को बंद होगा। कंपनी के शेयर बीएसई लिमिटेड (बीएसई एसएसई) के एसएसई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होंगे। इस इश्यू के माध्यम से जुटाए गए धन का उपयोग व्यवसाय विस्तार के लिए किया जाएगा जिसमें मशीनरी खरीदना, फैक्ट्री निर्माण विस्तार, ऋणों का पुनर्भुगतान, कार्यशील पूंजी लगाना और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्य शामिल हैं। कम्फर्ट सिक्योरिटीज लिमिटेड इस इश्यू का बुक रनिंग लीड मैनेजर है। रु. 39.83 करोड़ के पब्लिक इश्यू में रु. 67-69 प्रति शेयर के प्राइज बैंड में रु.10 के 57,72,000 इक्विटी शेयरों का फेश इश्यू शामिल है। कंपनी ने पूंजीगत व्यय के लिए रु. 14 करोड़ का उपयोग करने की योजना बनाई है, जिसमें प्लास्टिक-फायर्ड लैंप्रेड बॉयलर की खरीद भी शामिल है, जो बिजली उत्पादन के लिए वेस्ट प्लास्टिक का उपयोग करेगा और बिजली की लागत को काफी कम करेगा। यह धनराशि स्टोरेज क्षमता बढ़ाने के लिए फैक्ट्री



हितेंद्र धनजी शाह
चेयरमैन, श्री एम पेपर बोर्ड्स लिमिटेड

बिल्डिंग विस्तार और उत्पादन गति बढ़ाने के लिए शीट कट्टर के अधिग्रहण का भी समर्थन करेगी। कार्यशील पूंजी के लिए रु. 10 करोड़ और टर्म लॉन पुनर्भुगतान के लिए रु. 7 करोड़ आवंटित किए जाएंगे, जिससे मैनेजमेन्ट सुचारू होगा, केश पलो मैनेजमेन्ट में सुधार होगा और ब्याज लागत कम होगी। शेष धनराशि का उपयोग सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों और इश्यू खर्च के लिए किया जाएगा। एप्लिकेशन के लिए न्यूनतम लॉट साइज 2,000 शेयर है जो प्रति एप्लिकेशन रु. 1.38 लाख के निवेश के बराबर है। आईपीओ के लिए रिटेल निवेशक कोटा शुद्ध ऑफर के 35 से कम नहीं रखा गया है, एचएनआई कोटा ऑफर के 15 से कम नहीं रखा गया है और क्यूआईबी हिस्सा ऑफर के 50 से अधिक नहीं रखा गया है। 1989 में स्थापित, श्री एम पेपर बोर्ड्स लिमिटेड आईएसओ-9001 प्रमाणित कंपनियों में से एक है, जो खाद्य और पेय पदार्थ, फार्मास्यूटिकल्स, सौंदर्य प्रसाधन और कन्ज्युमर गुड्स जैसे उद्योगों में विभिन्न पैकेजिंग एप्लिकेशन्स में उपयोग किए जाने वाले 200 से 500 क्वीएसएम तक के रिसायकल्ड पेपर-आधारित डुप्लेक्स बोर्ड प्रोडक्स के निर्माण के व्यवसाय में लगी हुई है। कंपनी



रूषभ हितेंद्र शाह
मैनेजिंग डायरेक्टर, श्री एम पेपर बोर्ड्स लिमिटेड

घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में अपने उच्च गुणवत्ता वाले डुप्लेक्स बोर्ड पेपर प्रोडक्स की आपूर्ति भी करती है। कंपनी द्वारा उत्पादित कोटेड डुप्लेक्स बोर्ड 100% रिसायकल्ड वेस्ट पेपर से बने होते हैं और पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जो उन्हें विभिन्न एफएमसीजी और फार्मास्यूटिकल सामानों की पैकेजिंग के लिए पर्यावरण-अनुकूल विकल्प बनाते हैं। महाराष्ट्र के चिपलुण में कंपनी की विनिर्माण सुविधा 30 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैली हुई है, इसकी स्थापित क्षमता 72,000 टन प्रति वर्ष (टीपीए) है, साथ ही 4 मेगावाट कैप्टिव पावर प्लांट भी है और यह अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित है जो दुनिया भर के पैकेजिंग क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंट कार्यों के लिए उपयुक्त वैश्विक गुणवत्ता मानक के पेपर बोर्ड का निर्माण करती है। देश भर में 25 से अधिक डीलरों के विशाल नेटवर्क और 15 से अधिक देशों में निर्यात परिचालन के साथ, श्री एम पेपर बोर्ड ने व्यापक बाजार पहुंच और एक मजबूत उद्योग उपस्थिति बनाए रखी है। 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए, कंपनी ने परिचालन से राजस्व रु. 272.23 करोड़, एबिटा रु. 27.07 करोड़ और शुद्ध लाभ रु. 11.35 करोड़ दर्ज किया।

पैकेजिंग सामग्री बनाने वाली प्रमुख कंपनी है ‘सती पॉली प्लास्ट लिमिटेड’ 12 जुलाई को खुलकर 16 जुलाई 2024 को बंद होगा कंपनी का आईपीओ



बिजनेस रेमेडीज/जयपुर। भागलपुर आधारित सती पॉली प्लास्ट लिमिटेड बहुक्रियाशील लचीली पैकेजिंग सामग्री बनाती है जो विभिन्न उद्योगों की पैकेजिंग आवश्यकताओं को पूरा करती है। कंपनी द्वारा कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एनएसई इमर्ज प्लेटफार्म पर आईपीओ लाया जा रहा है। बिजनेस रेमेडीज की टीम ने कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स से कंपनी की कारोबारी गतिविधियों के संबंध में जानकारी हासिल की। **कंपनी की कारोबारी गतिविधियां:** जुलाई 1999 में स्थापित, सती पॉली प्लास्ट लिमिटेड बहुक्रियाशील लचीली पैकेजिंग सामग्री बनाती है जो विभिन्न उद्योगों की पैकेजिंग आवश्यकताओं को पूरा करती है। कंपनी ने दो विनिर्माण इकाइयां स्थापित की हैं। प्लांट 1 गौतमबुद्ध नगर, नोएडा में स्थित है, और प्रति माह 540 टन का उत्पादन कर सकता है। प्लांट 2 उद्योग केंद्र, नोएडा में स्थित है और इसकी स्थापित क्षमता 540 टन प्रतिमाह है। कंपनी ने 2018 और 2019 के बीच अपनी स्थापित क्षमता को लगातार 250 टन प्रति माह से बढ़ाकर 500 टन प्रति माह कर दिया है। कंपनी

प्रवर्तकों का अनुभव
62 वर्षीय बालमुकुंद झुनझुनवाला कंपनी के प्रमोटर,अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं।उन्होंने कंपनी की कॉर्पोरेट इकाई की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और पैकेजिंग उद्योग के भीतर उनके पास लगभग 6 वर्षों की व्यापक विशेषज्ञता है।

36 वर्षीय आदित्य झुनझुनवाला कंपनी के प्रमोटर और कार्यकारी निदेशक और सीईओ हैं। उन्होंने एमिटी यूनिवर्सिटी, नोएडा से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन- इंटरनेशनल बिजनेस में डिग्री प्राप्त की है। उनके पास व्यवसाय विस्तार, विपणन पहल, व्यवहार्य बाजारों की पहचान और पैकेजिंग उद्योग में रणनीतिक योजना के क्षेत्र में 6 (छह) वर्षों का अनुभव है। उनकी विशेषज्ञता विपणन योजनाओं के निर्माण, ग्राहकों का प्रतिनिधित्व और कंपनी के उद्देश्यों से संबंधित लक्षित दर्शकों और बाजारों की समझ तक फैली हुई है।

23 वर्षीया केशव झुनझुनवाला कंपनी की प्रमोटर एवं गैर-कार्यकारी निदेशिका हैं। उनके पास भारती विद्यापीठ (मानित विश्वविद्यालय),पुणे से मार्केटिंग मैनेजमेंट में बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री है। उन्होंने हाल ही में कंपनी के साथ जुड़ाव शुरू किया है।

60 वर्षीया कंपनी प्रवर्तिका अनिता झुनझुनवाला कंपनी की प्रमोटर हैं। उनके पास राजस्थान विश्वविद्यालय से कला स्नातक की डिग्री है।

गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब और राजस्थान,असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव दिल्ली जैसे राज्यों में अपनी पैकेजिंग सामग्री की आपूर्ति करती है। कंपनी के ग्राहकों में पिडिलाइट, अदानी विल्मर और जेवीएल शामिल हैं। 31 मार्च 2024 तक, कंपनी में कुल 135 ऑन रोल कर्मचारी थे। **वित्तीय प्रदर्शन:** वित्त वर्ष 2022 में कंपनी ने कुल राजस्व 175.22 करोड़ रुपए एवं 28.23 लाख रुपए का कर पश्चात शुद्ध लाभ, वित्त वर्ष 2023 में कंपनी ने कुल राजस्व 190.96 करोड़ रुपए एवं 3.08 करोड़ रुपए का कर पश्चात शुद्ध लाभ और वित्त वर्ष 2024 में 179.40 करोड़ रुपए का राजस्व एवं 3.28 करोड़ रुपए का कर पश्चात शुद्ध लाभ अर्जित किया है। कंपनी के वित्तीय परिणामों से स्पष्ट है कि कंपनी का राजस्व एवं लाभ वर्ष दर वर्ष बढ़ रहा है।

IPO Date	July 12, 2024 to July 16, 2024
Listing Date	July 22, 2024
Face Value	₹10 per share
Price Band	₹123 to ₹130 per share
Lot Size	1000 Shares
Total Issue Size	1,335,000 shares (aggregating up to ₹17.36 Cr)
Fresh Issue	1,335,000 shares (aggregating up to ₹17.36 Cr)
Issue Type	Book Built Issue IPO
Listing At	NSE SME
Share holding pre issue	3,612,000
Share holding post issue	4,947,000
Market Maker portion	70,000 shares Spread X Securities

वित्त वर्ष 2024 में कंपनी का कर पश्चात शुद्ध लाभ मार्जिन 1.83 फीसदी दर्ज किया गया है। वित्त वर्ष 2024 में कंपनी की कुल असेट्स 56.37 करोड़ रुपए, नेटवर्थ 12.30 करोड़ रुपए, रिजर्व एंड सरप्लस 8.69 करोड़ रुपए और कुल कर्ज 25.20 करोड़ रुपए दर्ज किया गया है। **आईपीओ के संबंध में जानकारी:** ‘सती पॉली प्लास्ट लिमिटेड’ का आईपीओ 12 जुलाई को एनएसई इमर्ज प्लेटफार्म पर खुलकर 16

जुलाई 2024 को बंद होगा। कंपनी द्वारा 10 रुपये फेसवैल्यू के 13,35,550 शेयर बुक इश्यू प्रणाली से 123 रुपए से 130 रुपए प्रति शेयर के भाव पर जारी कर 17.36 करोड़ रुपए जुटाए जा रहे हैं। आईपीओ का मार्केट लॉट साइज 1000 शेयरों का है। आईपीओ का प्रबंधन प्रमुख लीड मैनेजर कंपनी बीलाईन एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। **नोट: यह लेख निवेश सलाह नहीं है।**

पुरुषों के सौंदर्य के लिए उत्पाद पेश करने वाली प्रमुख कंपनी है ‘मैकॉब्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड’ 16 जुलाई को खुलकर 19 जुलाई 2024 को बंद होगा कंपनी का आईपीओ



बिजनेस रेमेडीज/जयपुर। जयपुर आधारित ‘मैकॉब्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड’ पुरुषों के सौंदर्य के लिए उत्पाद पेश करने वाली प्रमुख कंपनी है। कंपनी द्वारा ग्राहक अधिग्रहण - विपणन और जागरूकता पर पूंजी खर्च करने, कंपनी द्वारा लिए गए कुछ बकाया उधारों के एक हिस्से का पूर्व भुगतान या पुनर्भुगतान करने, कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एनएसई इमर्ज प्लेटफार्म पर आईपीओ लाया जा रहा है। बिजनेस रेमेडीज की टीम ने कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स से कंपनी की कारोबारी गतिविधियों के संबंध में जानकारी हासिल की। **यह करती है कंपनी:** मैकॉब्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की स्थापना 2019 में हुई थी और यह पुरुषों के सौंदर्य के लिए उत्पाद पेश करती है। कंपनी अपनी वेबसाइट <https://menhood.in/> के माध्यम से मांग वाले क्षेत्रों के लिए विशेष ट्रिगर, पुरुषों की त्वचा के अनुरूप स्वच्छता उत्पाद, ब्रीफ और विभिन्न

प्रकार की स्व-देखभाल वस्तुएं प्रदान करती है। कंपनी के पास भौतिक स्टोर या पारंपरिक खुदरा उपस्थिति नहीं है। **कंपनी की ताकत:** विशिष्ट बाजारों को लक्षित करना: पुरुषों की अंडर-द-बेल्ट ग्रूमिंग पर ध्यान केंद्रित करके, कंपनी इस बाजार पर फोकस कर रही है और इस क्षेत्र की बड़े पैमाने पर उपेक्षा हुई है। **ई-कॉमर्स रणनीति:** विशेष रूप से ऑनलाइन संचालन करने से बाजार तक पहुंच बढ़ती है, ओवरहेड्स कम होते हैं और परिचालन लचीलापन मिलता है। इसलिए कंपनी ने वेबसाइट के माध्यम से बाजार में पहुंच बनाने की कोशिश की है। **नवीन उत्पाद श्रृंखला:** कंपनी ने विशिष्ट सौंदर्य आवश्यकताओं के लिए विशेष उत्पाद विकसित किए हैं जिससे एक विशेष बाजार की मांग पूरी होती है। ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण: ग्राहकों की जरूरतों और प्राथमिकताओं के साथ-साथ सक्रिय जुड़ाव और फीडबैक पर जोर देने से ग्राहक संबंध मजबूत होते

प्रवर्तकों का अनुभव
27 वर्षीय कंपनी प्रवर्तक दुष्यंत गंडोत्रा ने 21 साल की उम्र में अपनी उद्यमिता यात्रा शुरू की थी। वे साज-सज्जा के उद्योग में नवाचार और परिवर्तन में सबसे आगे रहने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे मैकॉब्स के प्रबंध निदेशक हैं और नवीन विचारों के साथ व्यक्तिगत सौंदर्य को प्रभावित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिससे व्यवसाय में निरंतर सुधार होता है। उनके नवीन विचारों से कंपनी को गोथ करने में मदद मिलती है। उनके पास नए नवीन विचार बनाने का अनुभव है। वे सेंट जेवियर्स कॉलेज से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातक हैं।

31 वर्षीय कंपनी प्रवर्तक शिवम भटेजा ने मैकॉब्स के सह-संस्थापक होने से पहले प्रदर्शन विपणन और बिजनेस ऑटोमेशन में 10 वर्षों से अधिक का विविध अनुभव अर्जित किया, जिससे उनकी उद्यमशीलता यात्रा की दिशा में एक मजबूत नींव स्थापित हुई। वर्तमान में वे मैकॉब्स में पूर्णकालिक निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। वे कंपनी की रणनीतिक योजना बनाने में योगदान देते हैं। वे कंपनी के मिशन और विज़न के साथ दीर्घकालिक लक्ष्यों को जोड़ते हैं जो मैकॉब्स को एक प्रमुख और प्रभावशाली ब्रांड के रूप में स्थापित करने में मदद करता है।

31 वर्षीया कंपनी प्रवर्तक दिव्या गंडोत्रा, ईएमआईएसी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड का नेतृत्व करती हैं और वे कंटेंट मार्केटिंग और ग्राहक संबंधों पर ध्यान केंद्रित करती हैं। वे ब्रांड दृश्यता पहल को आगे बढ़ाती हैं। उन्होंने कंप्यूटर विज्ञान, विपणन और कानून विषय में शिक्षा हासिल की है।

हैं। इसलिए कंपनी ने ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया है। **शैक्षिक सामग्री रणनीति:** पुरुष सौंदर्य के लिए विशेष उत्पाद विकसित किए हैं जिससे एक विशेष बाजार की मांग पूरी होती है। ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण: ग्राहकों की जरूरतों और विश्वास बनाने में मदद करती है। इस संबंध में जागरूकता के लिए कंपनी ने शैक्षिक सामग्री की रणनीति अपनाई है। स्थिरता और नैतिकता: कंपनी की पर्यावरण-अनुकूल पैकेजिंग और टिकाऊ सोर्सिंग के प्रति प्रतिबद्धता पर्यावरण और सामाजिक जिम्मेदारी पर बढ़ते उपभोक्ता फोकस के अनुरूप है। कंपनी के पास 15 फुल टाइम कर्मचारी कार्यरत हैं। **वित्तीय प्रदर्शन:** वित्त वर्ष 2022 में कंपनी ने कुल राजस्व 6.02 करोड़

रुपए एवं 38.89 लाख रुपए का कर पश्चात शुद्ध लाभ, वित्त वर्ष 2023 में 14.82 करोड़ रुपए का राजस्व एवं 2.04 करोड़ रुपए का कर पश्चात शुद्ध लाभ और वित्त वर्ष 2024 में कंपनी ने 20.74 करोड़ रुपए का राजस्व एवं 2.21 करोड़ रुपए का कर पश्चात शुद्ध लाभ अर्जित किया है। कंपनी के वित्तीय परिणामों से स्पष्ट है कि कंपनी का राजस्व एवं लाभ वर्ष दर वर्ष बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 2024 में कंपनी का कर पश्चात शुद्ध लाभ मार्जिन 10.73 फीसदी दर्ज किया गया है। वित्त वर्ष 2024 में कंपनी की कुल असेट्स 14.43 करोड़ रुपए, नेटवर्थ 7.20 करोड़ रुपए, रिजर्व एंड सरप्लस 2.62 करोड़ रुपए और कुल कर्ज 2.50 करोड़ रुपए दर्ज किया गया है। नेटवर्थ के मुकाबले कंपनी का कर्ज काफी कम है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि कंपनी पर कर्ज भार ना के बराबर है। **आईपीओ के संबंध में जानकारी:** ‘मैकॉब्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड’ का आईपीओ एनएसई इमर्ज प्लेटफार्म पर 16 जुलाई को खुलकर 19 जुलाई 2024 को बंद होगा। कंपनी द्वारा बुक बिल्ट इश्यू प्रणाली से 10 रुपये फेसवैल्यू के 25,95,200 शेयर 71 रुपए से 75 रुपए प्रति शेयर के भाव पर जारी कर 19.46 करोड़ रुपए जुटाए जा रहे हैं। आईपीओ का मार्केट

IPO Date	July 16, 2024 to July 19, 2024
Listing Date	July 24, 2024
Face Value	₹10 per share
Price Band	₹71 to ₹75 per share
Lot Size	1600 Shares
Total Issue Size	2,595,200 shares (aggregating up to ₹19.46 Cr)
Fresh Issue	2,595,200 shares (aggregating up to ₹19.46 Cr)
Issue Type	Book Built Issue IPO
Listing At	NSE SME
Share holding pre issue	7,200,000
Share holding post issue	9,795,200
Market Maker portion	131,200 shares SKI Capital Services

लॉट साइज 1600 शेयरों का है। आईपीओ का प्रबंधन प्रमुख लीड मैनेजर कंपनी एसकेआई कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। **नोट: यह लेख निवेश सलाह नहीं है।**

महिंद्रा ने BS6 OBD II ट्रकों की अपनी पूरी रेंज के लिए शुरु की माइलेज गारंटी

बिजनेस रेमेडीज/पुणे। महिंद्रा समूह की इकाई महिंद्रा ट्रक और बस डिवीजन (एमटीबीडी) ने BLAZO X, FURIO, OPTIMO & JAYO ट्रकों की अपनी पूरी BS6 OBD II रेंज के लिए एक शानदार कस्टमर वैल्यू प्रीपोजीशन की घोषणा की है। कमर्शियल वाहन उद्योग में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए महिंद्रा ने इस पहल को ‘अधिक माइलेज हासिल करें या ट्रक वापस दें’ नाम दिया है। इस पहल में एचसीवी, आईसीवी और एलसीवी ट्रकों को शामिल किया गया है। इंडस्ट्री की यह अग्रणी पहल ईंधन की बरती कीमतों और विकसित नियामक मानकों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए शुरू की गई है। नई रेंज में प्यूनस्मार्ट तकनीक के साथ प्रमाणित 7.2 एमपावर इंजन (एचसीवी) और एमडीआई टेक इंजन (आईएलसीवी), प्रमाणित आपटर

ट्रीटमेंट सिस्टम के साथ माइल्ड ईंजीआर शामिल है, जिसके परिणामस्वरूप एड ब्लू की खपत कम होती है। साथ ही इनमें अन्य अनेक टैक्नोलॉजी संबंधी एडवॉंस्मेंट भी जोड़े गए हैं और अत्याधुनिक iMAXX टेलीमैटिक्स समाधान भी है, जो गारंटीड उच्च माइलेज सुनिश्चित करते हैं। इस माइलेज गारंटी में न केवल प्यून एफिशिएंसी शामिल है, बल्कि इसमें सबसे कम एड ब्लू खपत का संयोजन भी है, इसलिए सही मायने में महिंद्रा की माइलेज गारंटी का मतलब है श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ ‘प्लुइड एफिशिएंसी’। टैक्नोलॉजी संबंधी एडवॉंस्मेंट के बेहतर नतीजों को सुनिश्चित करने के लिए, महिंद्रा ने 21 उत्पाद श्रेणियों में प्लुइड एफिशिएंसी (डीजल प्लस एड ब्लू) परीक्षण किए, जिसमें प्रतिस्पर्धियों के वाहनों सहित 71 मॉडल शामिल थे।



इन परीक्षाओं के दौरान, जो 1 लाख किलोमीटर से अधिक तक चले और जिसमें विभिन्न प्रकार के भार और सड़क की स्थिति शामिल थी, महिंद्रा ने असाधारण माइलेज प्रदर्शन प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। ये सभी परीक्षण एक स्वतंत्र विश्वसनीय एजेंसी की देखरेख में किए गए और उनके द्वारा मान्य किए गए। परिणाम ने

वाणिज्यिक वाहन उद्योग में निर्भरता और दक्षता के लिए महिंद्रा की प्रतिष्ठा को मजबूत किया है। इस बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए, प्रेसिडेंट ऑफ ट्रक्स, बसेज, सीई, एयरोस्पेस और डिफेंस बिजनेस, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड और मेंबर, ग्रुप एक्जीक्यूटिव बोर्ड, महिंद्रा ग्रुप विनोद सहाय ने कहा, “ट्रक रेंज में ‘अधिक

माइलेज हासिल करें या ट्रक वापस दें’ गारंटी एक ऐतिहासिक कदम है जो हमारी बेहतर उच्च तकनीक विशेषज्ञता, सेगमेंट की गहन समझ और हमारे ग्राहकों की उभरती जरूरतों को दर्शाता है। यह माइलेज गारंटी कार्यक्रम प्लुइड एफिशिएंसी टेस्ट द्वारा समर्थित है, जो ग्राहक संतुष्टि और परिचालन दक्षता के लिए हमारी अद्वि प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ऐसी पहलों के साथ, महिंद्रा ग्राहकों के दिल को जीतने और भारत की अग्रणी वाणिज्यिक वाहन कंपनी बनने के लिए अचछी स्थिति में है।

महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के बिजनेस हैड-कमर्शियल व्हीकल्स जलज गुप्ता ने कहा, “हमारे वाहनों की बेहतर तकनीकी प्रगति के परिणामस्वरूप हायर प्लुइड एफिशिएंसी साबित हुई है। 2016 में हमने BS3 रेंज में माइलेज गारंटी लॉन्च की थी। इसके बाद हमने

इसे BS4 &BS6 OBD1 में जारी रखा और अब BS6 OBD2 में लॉन्च कर रहे हैं, जो ट्रांसपोर्टरों की लाभप्रदता बढ़ाने में मदद करेगा। हम जानते हैं कि ईंधन की लागत में वृद्धि के बावजूद माल ढुलाई दरों में वृद्धि नहीं हुई है और हमने परिवहन ग्राहकों के मार्जिन पर बढ़ते प्रभाव को देखा है। इसीलिए हमने नए मानकों को पूरा करने और ग्राहकों की अपेक्षाओं से भी आगे बढ़ने के लिए इंजन अपेक्षाओं का वादा कर रहे हैं। हमें यकीन है कि यह गारंटी हमारे ग्राहकों को बहुत उपयोगी साबित होगी। इसके अलावा, महिंद्रा ट्रक्स में iMAXX टेलीमैटिक्स तकनीक है, जिसके जरिये बेड़े के संचालन की वास्तविक समय की निगरानी की जा सकती है। इन ट्रकों में

एक ड्राइवर इन्फॉर्मेशन सिस्टम भी शामिल है, जो वाहन के प्रदर्शन और चालक के आचरण की वास्तविक समय की निगरानी की अनुमति देती है, जिससे सुरक्षित और कुशल संचालन सुनिश्चित होता है। यह प्रणाली ग्राहकों को उनके बेड़े के कामकाज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देती है, जिससे वे बेहतर निर्णय ले सकते हैं और अधिक से अधिक लाभ हासिल कर सकते हैं। महिंद्रा अपने ग्राहकों की सुविधा और उनकी मानसिक शांति के लिए अनेक अन्य स्कीम भी संचालित करता है। इनमें प्रमुख हैं- वर्कशॉप में 36 घंटे का गारंटीकृत टर्नअराउंड, एमआश्रय प्रोग्राम के तहत ड्राइवरों के लिए पांच लाख रुपये का कैजुअल्टी कवरेज और आपातकालीन स्थिति में ट्रक ड्राइवरों के लिए कई भाषाओं में 24/7 सहायता, इत्यादि।

भारत की सड़कों पर चल रही हैं टाटा मोटर्स की 20 लाख एसयूवी

बिजनेस रेमेडीज/मुंबई। टाटा मोटर्स, भारत में ऑटोमोटिव बनाने वाली अग्रणी और प्रमुख एसयूवी निर्माता कंपनी ने भारतीय सड़कों पर अपनी 2 मिलियन से ज्यादा एसयूवी ढौड़ने की एक ऐतिहासिक उपलब्धि का उत्सव मनाया है। कंपनी की एसयूवी का पोर्टफोलियो बड़ा है, जिसमें सफारी, हैरियर, नेक्सॉन, पंच और बीते वर्षों के मशहूर नेमालेड्स सिफार और सफारी भी शामिल हैं। यह उपलब्धि हासिल करने में इन सभी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन मजबूत एसयूवी में से हर किसी ने अपने सेगमेंट को नई परिभाषा दी है और यह टाटा मोटर्स का समर्पण दिखाती हैं। कंपनी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा, अत्याधुनिक डिजाइन और उन्नत टेक्नोलॉजी के लिये समर्पित है। यह ग्राहकों की उम्मीदों के मुताबिक है और इसलिये इन वाहनों को सचमुच ‘किंग ऑफ एसयूवी’ बनाता है। टाटा मोटर्स ने 1991 में

भारत में अपनी पहली एसयूवी टाटा सिफरा लॉन्च की थी। कंपनी ने 2014 ऑटो एक्सपो में



भारत का पहला कॉम्पैक्ट एसयूवी कॉन्सेप्ट नेक्सॉन दिखाया था। पंच के साथ कंपनी ने सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी की एक नई कैटेगरी पेश की और उसके पास 5 स्टार रेटेड बी-एनसीएपी और जी-एनसीएपी एसयूवी का सबसे बड़ा पोर्टफोलियो भी है। टाटा मोटर्स ने हमेशा अग्रणी रहने के उत्साह के साथ देश में एसयूवी की कैटेगरी को परिभाषित किया है।

इस खास मौके पर अपनी बात रखते हुए, टाटा पेंसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लि. के चीफ कॉर्पोरेट ऑफिसर विवेक श्रीवास्तव ने कहा,

“एसयूवी सेगमेंट को समझने और हर ग्राहक की जरूरत के लिये सही उत्पाद देने में हमारी क्षमता अपने सेगमेंट में स्थिर और अग्रणी बने रहने में हमारी काफी मदद करती है। अपनी मल्टी पावरट्रेन रणनीति की सहायता से हम भारतीय उपभोक्ताओं को विश्व-स्तरीय एसयूवी देना चाहते हैं। यह एसयूवी मजबूत, सुरक्षित और उन्नत टेक्नोलॉजी वाली होती हैं। 2 मिलियन एसयूवी बिक जाने की उपलब्धि हमारी यही इच्छा दिखाती है और एसयूवी कैटेगरी की भविष्य में होने वाली वृद्धि के लिये गति को तय करती है।” इस उपलब्धि का उत्सव मनाते हुए, हम किंग ऑफ एसयूवी फेस्टिवल के साथ अपने ग्राहकों तक यह खुशी पहुँचाकर उत्साहित हैं। हमने अपनी प्लेगेशिप एसयूवी की शुरुआती कीमतों को बदल दिया है, जैसे कि हैरियर (14.99 लाख रुपये) और सफारी (15.49 लाख रुपये)। हम एसयूवी के लोकप्रिय वैरिएंट्स पर 1.4 लाख रुपये तक के फायदे भी दे रहे हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों के मामले में, Nexon.ev के साथ शानदार लाभ मिल रहे हैं (1.3 लाख रुपये तक) और वह पहले से कहीं ज्यादा लोगों की पहुंच में हैं।

विधि

सिडबी और ब्लूस्मार्ट: 140 से अधिक इलेक्ट्रिक कारों को सवारी सेवा के लिए इंडी दिखाकर किया रवाना

बिजनेस रेमेडीज/नई दिल्ली। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इकोसिस्टम के लिए ईवी 4ईको योजना के तहत, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए देश की प्रमुख वित्तीय संस्था, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) और भारत की सबसे बड़ी ईवी राइडहेलिग सेवा, ब्लूस्मार्ट ने भारतीय सरकार और बहुपक्षीय संगठनों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में 140 से अधिक इलेक्ट्रिक कारों को इंडी दिखाकर रवाना किया। सिडबी का ABCD (Aaओ B नाए Cलीन Diल्ली) नारा दिल्ली की सड़कों पर इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाने के लिए है। सिडबी ने हरित क्षेत्रों में वित्तीय और विकासात्मक समर्थन प्रदान करने में विशेषज्ञता हासिल की है और अन्य ऋणदाताओं को उनके पूर्वाग्रहित जोखिमों को कम करने में भी समर्थन देता है ताकि ईवी के लिए अधिक ऋण प्रदान किया जा सके। दिल्ली ईवी नीति भारत की सबसे प्रगतिशील ईवी नीति रही है। प्रकाश कुमार, उप प्रबंध निदेशक, सिडबी ने कहा, ‘सिडबी, एक विकासपरक वित्तीय



संस्था (डीएफआई) होने के नाते, अपने विकासात्मक और वित्तीय प्रयासों के साथ उद्यमों के इकोसिस्टम को हरित बनाने के लिए सी य कदम उठा रही है। नए तकनीकों को एमएसएमई के बीच बढ़ावा देने में सिडबी हमेशा अग्रणी रही है। सिडबी कई गतिविधियों में संलग्न है और सभी मोर्चों पर इकोसिस्टम को हरित बनाने के क्षेत्र में अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार कर रही है, चाहे वह स्टार्टअप हो, एमएसएमई, गामीना/ असेवित/ अल्पसेवित खंड/ पॉकेट/ कारीगर क्लस्टर आदि हो। हमने ‘ग्रीन बैंक’ बनने की यात्रा शुरू की है। सिडबी ने इलेक्ट्रिक वाहन वित्तपोषण में प्रमुख चुनौतियों को समझा है

और इसलिए, ईवी इकोसिस्टम को समर्थन देने और ईवी स्टार्टअप के लिए वित्त को सुगम बनाने हेतु अनूठी योजनाएं बनाई हैं। सिडबी ब्लूस्मार्ट को उनकी शून्य उत्सर्जन सवारी सेवा की यात्रा में समर्थन देने के लिए हर्ष का अनुभव कर रही है। डॉ. आर.के. सिंह, मुख्य महाप्रबंधक, सिडबी ने कहा, ‘भारत ने जलवायु परिवर्तन शमन के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं और परिवहन क्षेत्र में न्यूनतम कार्बन वृद्धि के लिए प्रतिबद्धता जताई है। भारत की ईवी30@30 प्रतिबद्धता का समर्थन करने के लिए, ईवी मूल्य श्रृंखला में देशव्यापी परामर्श आयोजित करने की रणनीति बनाई गई थी। सिडबी ने

इलेक्ट्रिक वाहनों के सस्ते वित्तपोषण को सक्षम करने के लिए ईवी 4ईको और ईवी-आरएसएफ योजनाएं शुरू की हैं। इन पहलों से वाहन उत्सर्जन में कमी और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में परिचालन लागत में कमी आएगी।’ सिडबी ईवी30@30 को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और एमएसएमई को उनके संचालन में हरित तकनीक अपनाने में सहयोग कर रही है। हमने अन्य ऋणदाताओं के वित्तपोषण को सक्षम बनाने के लिए जोखिम को साझा करने सुविधा के माध्यम से प्रोत्साहित को कई अन्य पहल की तैयार है और ग्रामीण क्षेत्रों में महिला उद्यमियों को इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तन के लिए सस्ती वित्तपोषण प्रदान करने के लिए सक्रिय हैं। अनमोल जगगी, सह-संस्थापक, ब्लूस्मार्ट ने कहा, ‘ब्लूस्मार्ट में हमारा मिशन ‘मोबिलिटी को बड़े पैमाने पर डिकार्बोनाइज करना’ है और सिडबी अपनी अनूठी ABCD पहल के साथ हमारे विकास को दिल्ली एनसीआर में समर्थन दे रही है और परिवहन क्षेत्र से कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में ईवी को अपनाने के काम को तेज कर रही है।’

व्हाट्सऐप ने यूजर्स को सुरक्षित रखने के लिये ग्रुप मैसेजिंग में कंटेक्ट्स कार्ड की पेशकश की

बिजनेस रेमेडीज/नई दिल्ली। व्हाट्सऐप एक नया फीचर लेकर आ रहा है, जिससे यूजर्स को ग्रुप मैसेजिंग में सुरक्षित रहने में मदद मिलेगी। अगर आपको किसी अनजान व्यक्ति ने एक ग्रुप में जोड़ा है, तो अब आपको उस ग्रुप के बारे में ज्यादा जानकारी देने वाला एक कंटेक्ट्स कार्ड नजर आएगा।

इस कार्ड से आपको पता चलेगा कि आपको ग्रुप में किसने जोड़ा, वह ग्रुप कब बना और उसे किसने बनाया। फिर आप फैसला कर सकते हैं कि आपको ग्रुप में रहना है या नहीं। आप व्हाट्सऐप पर सुरक्षित रहने के लिये उपलब्ध कुछ सेफ्टी टूल्स को रिव्यू भी कर सकते हैं।

यह खासकर तब मदद करता है, जब आप किसी व्यक्ति या लोगों के एक



समूह से हाल ही में जुड़े हों, लेकिन आपने उन्हें अपने कॉन्टैक्ट में सेव नहीं किया है। या इससे पुष्टि होती है कि आप उस ग्रुप को जानते हैं या नहीं अथवा उसमें रहना चाहते हैं या नहीं। यह अपडेट व्हाट्सऐप यूजर्स को सुरक्षा की एक और परत प्रदान करता है। इसे मौजूदा फीचर्स, जैसे कि अनजाने कॉलर्स को म्यूट करना , चैट लॉक ,इन-ऐप प्राइवेसी चेक-अप और

यह तय करना कि कौन आपको ग्रुप में ऐड कर सकता है के आधार पर बनाया गया है। यह 1:1 मैसेजिंग के मौजूदा अनुभव के समान है, जिसमें यदि कोई अनजान व्यक्ति आपको मैसेज करता है तो आपको ज्यादा कंटेक्ट दिए जाते हैं। यह फीचर यूजर्स को मिलने की लगा है और आने वाले हफ्तों में सारे यूजर्स के लिये उपलब्ध होगा।

एथर एनर्जी के सीईओ तरुण मेहता ने भारत में ट्रांसपोर्टेशन के पूर्ण इलेक्ट्रिफिकेशन के अमिताभ कांत के आह्वान का समर्थन किया

बिजनेस रेमेडीज/नई दिल्ली। एथर एनर्जी के सीईओ, तरुण मेहता ने भारत में सभी ट्रांसपोर्टेशन सेवाओं के इलेक्ट्रिफिकेशन की गंभीर जरूरत पर बल देने वाले अमिताभ कांत द्वारा हाल ही में दिए गए बयान का समर्थन किया है। मेहता ने एक दृवीट में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) में परिवर्तन के महत्व पर जोर दिया ताकि जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता और उत्सर्जन में कमी लाई जा सके, उनका यह बयान अमिताभ कांत के उद्देश्य के अनुरूप है।

तरुण मेहता ने अपनी दृवीट में कहा, “नीति आयोग के पूर्व सीईओ, अमिताभ कांत ने एक बार फिर भारत में सभी परिवहन सेवाओं के इलेक्ट्रिफिकेशन की आपात जरूरत का बिन्दुक सही आह्वान किया है। उद्योग में विरोधी तत्व नई



अमिताभ कांत नीति आयोग के पूर्व सीईओ

टेक्नोलॉजी की कमियाँ निकालते रहेंगे, लेकिन जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता और उत्सर्जन में कमी लाने के लिए 100 फीसदी इलेक्ट्रिफिकेशन से ज्यादा शक्ति शाली और कोई उपाय नहीं है। इलेक्ट्रिफिकेशन और सौर एवं पवन ऊर्जा द्वारा बिजली उत्पादन



का ग्रीनिफिकेशन आज हमारे देश के लिए एक सरल और बहुत शक्ति शाली उपाय है।” उन्होंने भारतीय इलेक्ट्रिक दू-व्हीलर (ई2डब्लू) उद्योग की अपार क्षमता पर बल देते हुए कहा कि भारत टेक्नोलॉजिकल

और सामाजिक परिवर्तन में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। मेहता ने कहा, “हमारा उद्योग दुनिया में कई दूव्हीलर दिग्गजों से पहले इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण, डिजाइन, आरएंडडी, और पुर्जों में निवेश कर रहा है, और आज हम विश्व में दूव्हीलर उद्योग में आ रही इस क्रांति का नेतृत्व कर सकते हैं। तरुण मेहता ने ईवी उद्योग का सहयोग करने में सरकारी नीतियों की महत्वपूर्ण भूमिका को भी स्वीकार किया। उन्होंने कहा, “2021 में जब सरकार अनुकूल ईवी नीतियाँ लेकर आई, तो उससे नए ईवी उद्योग को काफी महत्वपूर्ण मदद मिली। यह मदद ग्राहकों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन को व्यवहारिक बनाने के लिए बहुत आवश्यक थी, साथ ही इससे ईवी स्टार्टअप को आरएंडडी में निवेश करने

की सामर्थ्य भी मिली।” मेहता ने यह भी कहा कि टेक्नोलॉजिकल प्रगति के बाद भी ग्राहकों द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने की दर 5 से 6 प्रतिशत है, और इस क्षेत्र में लगातार सहयोग आवश्यक है। उन्होंने कहा, “मांग के प्रोत्साहन इसके लिए आवश्यक हैं क्योंकि खर्च किए गए हर रुपये के लिए उनका आउटपुट सबसे ज्यादा होता है। मांग में तेजी आने से ज्यादा क्षमताएं, ज्यादा इन्फ्रास्ट्रक्चर, ज्यादा आरएंडडी, ज्यादा उत्पाद, ज्यादा सप्लायर, और एक बड़ा परिवेश संभव हो सकेगे। उन्होंने भारत को विश्व में इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए स्थानीयकरण के महत्व पर बल दिया। मेहता ने कहा, “स्थानीयकरण

को बढ़ावा देकर हम आयातित पुर्जों पर अपनी निर्भरता कम कर सकेगे और एक आत्मनिर्भर उद्योग का विकास कर सकेगे, जो निर्यात में वृद्धि करे और ईवी क्रांति में ग्लोबल लीडर के रूप में भारत की स्थिति मजबूत कर सके। तरुण मेहता की दृवीट अमिताभ कांत द्वारा हाल ही में लिखे गए एक लेख की प्रतिक्रिया में आई थी, जिसमें कांत ने भारत के पाँच सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों को 2030 तक पूरी तरह से इलेक्ट्रिफाई करने की एक विस्तृत रणनीति का आह्वान किया था। अमिताभ कांत के अनुसार इस परिवर्तन द्वारा 2030 तक 10 बिलियन डॉलर की बचत की जा सकेगा और लाखों नौकरियों का निर्माण हो सकेगा, जिससे भारत विश्व में अग्रणी ईवी निर्माता के रूप में स्थापित हो सकेगा।